▸▸ वर्ष : 34 ▸▸ अंक : 375 ▸▸ मुंबई, मंगलवार, 24 मार्च 2026 ▸▸ RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸ मूल्य : 3 रुपए ▸▸ epaper.dobajedopahar.com ▸▸ संपादक : अरुण लाल ▸▸ संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

- अशोक खरात के खिलाफ दुष्कर्म के दो और मामले दर्ज
- आरोपी बाबा को पहले ही एक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस
- ज्योतिष खरात के खिलाफ विधानसभा में स्थगन खारिज
- दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा : फडणवीस

डराने के लिए दिखाता था नकली सांप

पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी खरात लोगों को डराने-धमकाने के लिए 20 फुट लंबे रिमोट से नियंत्रित नकली सांप और नकली बाघ की खाल का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा, वह लोगों को ठगने के लिए इमली के बीजों को 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था, उन्हें पॉलिश करवाकर कीमती रत्न बताकर 10 हजार रुपये में बेच देता था।

आज बड़ा खुलासा करेंगे सीएम फडणवीस

मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को बताया कि अशोक खरात की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। 10 मार्च को एक अन्य जिले में मिली शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया था। फडणवीस ने कहा, "शुरुआत में महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से डर रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का पुख्ता भरोसा दिया।" उन्होंने यह भी खुलासा किया कि खरात के खिलाफ पहले ही लुक-आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। मुख्यमंत्री मंगलवार को इस मामले पर सदन में विस्तृत बयान देंगे।

भोंदू बाबा का पाप लोक

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/नासिक

महाराष्ट्र के नासिक जिले में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ दो और मामले दर्ज किए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि ये नए मामले खरात द्वारा कथित तौर पर सात महीने की गर्भवती महिला और एक अन्य महिला का यौन शोषण करने से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि खरात ने नवंबर 2023 और दिसंबर 2025 के बीच अपने 'कनाडा कॉर्नर' स्थित दफ्तर में गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने महिला को कुछ खास पूजा-पाठ कराकर स्वस्थ संतानें होने का झांसा दिया था। वहीं, दूसरे मामले में एक अन्य महिला की शादी टूटने के बाद आरोपी ने दोबारा शादी करवाने का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। इससे पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस आरोपी खरात को गिरफ्तार कर चुकी है।

विधानसभा में संग्राम

नाशिक के स्वयंभू ज्योतिषी अशोक खरात के अनैतिक और काले कारनामों ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सोमवार (23 मार्च 2026) को विधानसभा में विपक्ष (कांग्रेस) ने इस मुद्दे पर 'स्थगन प्रस्ताव' पेश कर सदन की कार्यवाही रोकने की मांग की। हालांकि प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

विपक्ष की सीडीआर जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार (कांग्रेस) ने मामले को बेहद संगीन बताते हुए केवल एसआईटी जांच को नाकाफी बताया। उन्होंने मांग की कि इस ज्योतिषी के संपर्क में रहने वाले मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और महिला आयोग की अध्यक्ष के मोबाइल फोन के सीडीआर की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने मांग की कि इस घिनौने कृत्य में शामिल सभी रसूखदारों को तुरंत पदों से हटाया जाए। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के नेता भास्कर जाधव ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले के तार कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ IAS-IPS अधिकारियों से जुड़े हैं। जाधव ने सरकार पर पुराने मामलों को दबाने का आरोप लगाते हुए मांग की कि इस बार सच्चाई सामने आनी चाहिए और सदन में इस पर खुली चर्चा हो।

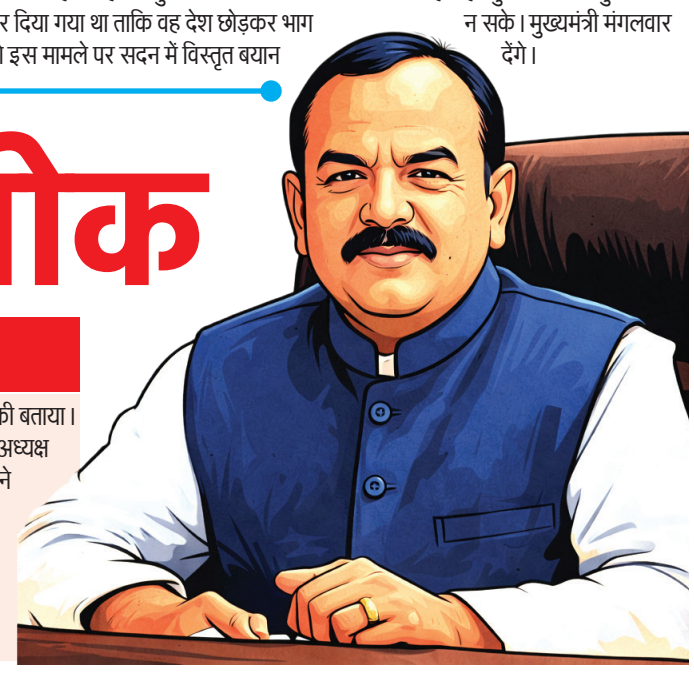

महिला आरक्षण कानून को लागू करने की तैयारी

लोकसभा में अब 543 नहीं, 816 सांसद

लोकसभा में इससे 816 सीटें हो जाएगी और उनमें 273 आरक्षित हो सकेंगी। सरकार ने मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही इस तरह के संकेत दिए थे। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सरकार ने इस बारे में संसद में विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श शुरू कर दिया है।

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में जल्द से जल्द 33 फीसद आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संशोधन लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार इस कानून को नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन के बजाए पिछली जनगणना के आधार पर ही लागू करना चाहती है, ताकि 2029 को लोकसभा चुनाव में और उसके पहले होने वाले विधानसभा चुनावों में ही इसे लागू कर दिया जाए। इसके लिए सदनों में 50 सीटों को बढ़ाने और उसमें 33 फीसद सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया जाएगा।

- संसद में विभिन्न दलों से सरकार ने शुरू की चर्चा, इसी सत्र में आ सकता है संशोधन विधेयक
- लोकसभा में हो जाएगी 816 सीटें, 273 होंगी महिलाओं के लिए आरक्षित

गृहमंत्री ने विपक्षी दलों से शुरू की चर्चा

सोमवार को बीजद, शिवसेना (यूबीटी, राकांपा (एसपी), वायएसआर कांग्रेस, एआईएमआईएम के नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की है। कांग्रेस और अन्य दलों से भी वह चर्चा करेंगे। इस बीच कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कहा है कि वह इसके खिलाफ नहीं हैं, चूंकि उन्होंने अभी यह विधेयक देखा नहीं है और उनसे चर्चा भी नहीं हुई है इसलिए वह चाहेंगे कि इस मुद्दे पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और चर्चा करे।

जनगणना की 'डेडलाइन' का झंझट खत्म

सूत्रों का कहना है कि सरकार इस सप्ताह के अंत में लोकसभा में संशोधन विधेयक ला सकती है, जिसमें वह 2023 में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करेगी और उसमें से नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन के बाद लागू करने का प्रावधान हटा देगी और इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का प्रावधान करेगी। उसी के आधार पर परिसीमन भी होगा, ताकि उत्तर व दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या को लेकर विवाद न बने। सरकार के सूत्रों का कहना है कि पिछली जनगणना कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुई थी, इसलिए उसे किसी तरह के आंकड़ों पर दिक्कत भी नहीं होगी।

तमिलनाडु में एनडीए का सीट शेयरिंग फाइनल

अन्नाद्रमुक 178, भाजपा 27, पीएमके 18 और एएमएमके 11 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

एजेंसी | नई दिल्ली

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सोमवार को सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा 234 सीटों में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में गठबंधन का नेतृत्व कर रही AIADMK 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पट्टाली मक्कल काची (PMK) को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) को 11 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि चंद्रशेखर के पास कोरमंगला में 49,000 स्क्वॉयर फीट का करीब 200 करोड़ रुपए का बंगला है, जिसकी जानकारी हलफनामें में छिपाई है।

पिछले चुनावी प्रदर्शनों का भी जिक्र

यह घोषणा अन्नाद्रमुक प्रमुख के पलानीस्वामी ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन शामिल हुए। इसके अलावा पुथिया नीधि काची के संस्थापक एसी षणमुगम ने कहा कि उन्होंने पीयूष गोयल को बीजेपी के 'कमल' चुनाव चिह्न के तहत नौ निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अपनी पार्टी की इच्छा के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने वेल्लोर में अपने पिछले चुनावी प्रदर्शनों का भी जिक्र किया।

सावधान! म्हाडा का 'लोगो' इस्तेमाल कर मजदूरों को ठग रहे डेवलपर

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई में घर का सपना देखने वाले मिल मजदूरों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है। सोमवार को विधानसभा में पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ कर दिया कि म्हाडा के नाम और उसके आधिकारिक 'लोगो' का गलत इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

▸▸ विधानसभा में गूंजा मिल मजदूरों के घरों का मुद्दा, शंभूराज देसाई ने दिए जांच के निर्देश

क्या है पूरा मामला?

सरकार ने शेलू और वांगनी इलाकों में मिल मजदूरों के लिए लगभग 81,000 घर बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक निजी डेवलपर (चड्ढा डेवलपर्स) को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन शिकायत मिली है कि यह डेवलपर म्हाडा के नाम और सरकारी 'लोगो' का इस्तेमाल कर मजदूरों से जबरन कंसेंट फॉर्म (सहमति पत्र) भरवा रहा है और उन्हें गलत जानकारी दे रहा है।

म्हाडा उपाध्यक्ष को जांच की कमान

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी निजी डेवलपर को मजदूरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने म्हाडा के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की तुरंत जांच करें और अगर डेवलपर दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत पुलिस केस दर्ज किया जाए। सरकार ने स्पष्ट किया कि 81 हजार घरों का प्रोजेक्ट मजदूरों के हित के लिए है।

ब्रीफ न्यूज़

अनिल अंबानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई-ईडी को लगाई फटकार

नई दिल्ली। रिलायंस एडीएजी समूह और अनिल अंबानी के खिलाफ चल रहे कथित 73,000 करोड़ रुपये के विशाल बैंकिंग घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार (23 मार्च 2026) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसियों (सीबीआई और ईडी) की सुस्ती पर कड़ा ऐतराज जताते हुए निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जांच एजेंसियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता का भरोसा तब बनेगा जब जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

पैरासिटामॉल समेत 90 दवा नमूने पाए गए अप्रमाणित

नई दिल्ली। देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने अप्रमाणित फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। नियामक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को 90 एफडीसी दवाओं की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार 2025 के सुगम लैब परीक्षण डाटा में बड़ी संख्या में दवाओं के सैंपल अप्रमाणित पाए गए हैं, जिन्हें नई दवा की श्रेणी में रखा गया है। नियमों के मुताबिक, किसी भी नई दवा का निर्माण और बिक्री बिना केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति के नहीं की जा सकती।

विधान परिषद चुनाव: महायुति का पलड़ा भारी, मविआ को बड़ा झटका

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब विधान परिषद में भी विपक्ष की ताकत काफी कम होने वाली है। आगामी 13 मई 2026 को उच्च सदन के 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा में मौजूदा दलीय स्थिति को देखते हुए, महाविकास आघाडी (MVA) इन 9 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाएगी। इसके विपरीत, महायुति की स्थिति और अधिक मजबूत होने के आसार हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में भाजपा के रणजीत सिंह मोहिते-पाटील, संजय केनेकर, संदीप जोशी और दादाराव केचे शामिल हैं। इसके अलावा नीलम गोऱ्हे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, राजेश राठौड़ और उद्धव ठाकरे का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इन सदस्यों को मंगलवार को औपचारिक विदाई दी जाएगी। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, महाविकास आघाडी के पास कुल 46 विधायक (उबाठा 20, कांग्रेस 16 और शरद पवार गुट 10) हैं।

अवैध उत्खनन पर कार्रवाई तेज

मुंबई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने सोमवार को विधानसभा में अवैध खनन और उत्खनन के खिलाफ बड़े अभियान की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों के भीतर आधुनिक तकनीक का उपयोग करके पूरे राज्य का ETS (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) सर्वेक्षण और गूगल मैपिंग किया जाएगा। विशेष रूप से ठाणे, पालघर, रायगढ़ और नवी मुंबई के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे अवैध उत्खनन की जांच के लिए SIT (विशेष जांच दल) का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व एक IPS अधिकारी और विभागीय आयुक्त करेंगे।

राज्य में बढ़े टीबी के मरीज

2 लाख 17 हजार से अधिक टीबी के मरीज मिले

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

विधानसभा में लिखित जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बताया कि वर्ष 2025 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान राज्य में 2,17,299 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में मरीजों की संख्या अधिक दिखने का मुख्य कारण व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे स्क्रीनिंग और सर्वे अभियान हैं, जिससे अधिक मामलों की पहचान हो पा रही है।

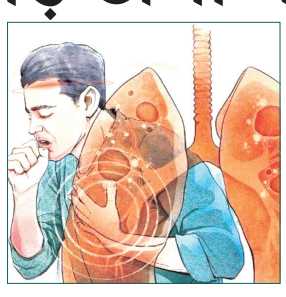

जांच बढ़ी, संक्रमण दर में लगातार गिरावट

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 9.54 लाख जांच में 20.98% मरीज मिले, जबकि 2025 में 45.71 लाख जांच के बावजूद यह दर घटकर 4.75% रह गई है। यह संकेत देता है कि संक्रमण की दर में कमी आ रही है। हालांकि, वायु प्रदूषण, घनी आबादी, खराब जीवन स्तर और कुपोषण जैसे कारण अब भी टीबी के प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं।

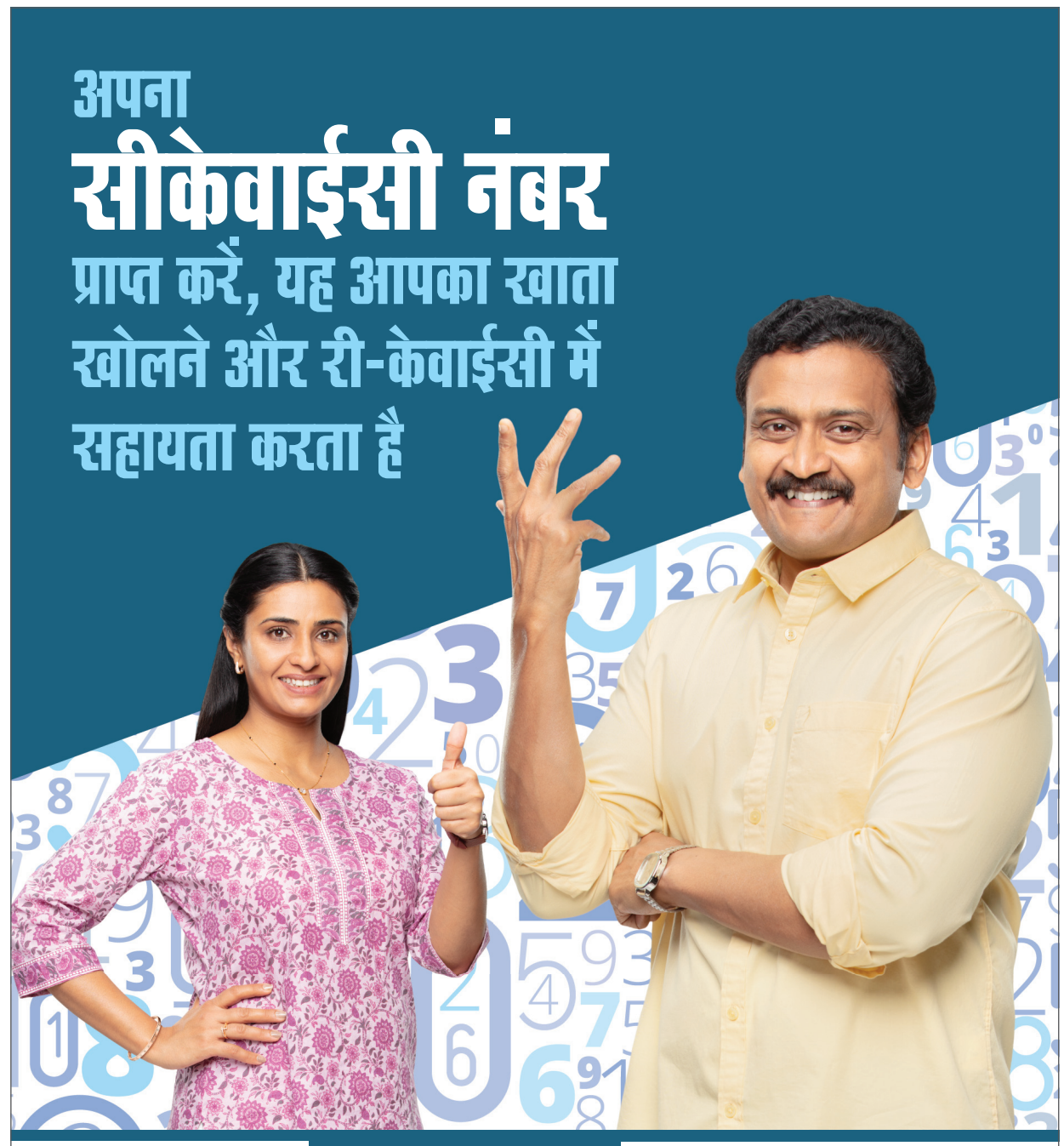

फार्मा यूनिट में केमिकल लीक

22 मजदूर अस्पताल में भर्ती

डीबीडी संवाददाता । पालघर

जिले के बोइसर स्थित तारापुर MIDC की एक फार्मा यूनिट में केमिकल लीक होने से 22 मजदूर बीमार हो गए। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सभी प्रभावितों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई।

यह हादसा रविवार दोपहर करीब 1:45 बजे उस समय हुआ, जब डाइ-मेथाइल सल्फेट (DMS) को टैंकर में भरा जा रहा था। इसी दौरान टैंकर की वेंट लाइन से केमिकल ओवरफ्लो होकर जमीन पर गिर गया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।

ऑपरेटर ने तत्परता दिखाते हुए लीकेज को तुरंत रोक दिया। इसके बाद लाइम और सोडा ऐश की मदद से करीब 2:30 बजे तक केमिकल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जिससे बड़े खतरे को टाल दिया गया। न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान उठे धुएं के कारण कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की आंखों में जलन और असहजता होने लगी। यही कारण रहा कि 22 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई।

मजदूरों की स्थिति खतरे से बाहर

शुरुआत में सभी मजदूरों को फैक्ट्री में ही निगरानी में रखा गया, लेकिन लक्षण बने रहने पर शाम करीब 7 बजे उन्हें बोइसर के अधिकारी लाइफलाइन मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है और किसी की जान को खतरा नहीं है। प्रशासन ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आसपास के क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

ठाणे का 'स्मार्ट' बजट

शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर फोकस, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाओं का वादा

6221 करोड़ का बजट पेश, बिना कर वृद्धि विकास पर जोर

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6221 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट बिना किसी कर वृद्धि के पेश किया। यह बजट मेयर शर्मिला पिंपोलकर की अध्यक्षता में आयोजित विशेष महासभा में प्रस्तुत किया गया। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने कहा कि बजट का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना और विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना है।

अमृत योजना से मिली अतिरिक्त सहायता

अमृत 2.0 योजना के तहत ऋण लेने की बजाय केंद्र सरकार से ब्याज मुक्त सहायता प्राप्त हुई, जिससे वित्तीय स्थिति को मजबूती मिली और परियोजनाओं को गति मिली।

खर्च में संतुलन और पूंजीगत निवेश बढ़ा

वर्ष 2025-26 में राजस्व और पूंजीगत खर्च के बीच संतुलन बनाए रखा गया, वहीं पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई। इससे बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिला।

2026-27 में संतुलित बजट और मामूली बचत

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व आय 4078 करोड़ रुपए है, जबकि कुल व्यय 6221 करोड़ 12 लाख रुपए प्रस्तावित है। इसमें राजस्व खर्च 3818 करोड़ 17 लाख रुपए और पूंजीगत खर्च 2401 करोड़ 55 लाख रुपए रखा गया है। बजट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की मामूली बचत का अनुमान भी जताया गया है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

चुनाव के बाद पहला बजट विकास पर फोकस

टीएमसी चुनाव के बाद यह पहला बजट है, जिसमें राजस्व बढ़ाने के प्रयासों के साथ विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार का संकल्प

मनपा के विद्यालयों को और अधिक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का संकल्प बजट में लिया गया है। शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है।

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं

बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू करने का वादा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

हरित शहर के निर्माण पर जोर

पर्यावरण संरक्षण और हरित शहर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प बजट में शामिल है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण और हरियाली बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

परिवहन सेवा के लिए अलग बजट

ठाणे परिवहन सेवा के लिए 791 करोड़ 86 लाख रुपए का अलग बजट भी पेश किया गया। यह बजट ट्रांसपोर्ट मैनेजर भालचंद्र बेहरे द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है।

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पेश हुआ बजट

बजट पेश किए जाने के दौरान डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी, हाउस लीडर हनमंत जगदाले, विपक्ष के नेता अशरफ शानू पठान सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

पिछले बजट में आय में गिरावट

आयुक्त सौरभ राव ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में कुछ विभागों की आय में कमी आई थी, जिसके चलते राजस्व आय को संशोधित कर कम किया गया। जलदाय, नगरीय विकास और अग्निशमन विभाग की आय में गिरावट देखी गई।

अनुदान में अपेक्षा से अधिक वृद्धि

हालांकि, अनुदान के मामले में मनपा को अपेक्षा से अधिक राशि प्राप्त हुई। जहां मूल बजट में 612 करोड़ रुपए का अनुमान था, वहीं दिसंबर 2025 तक 1269 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान प्राप्त हुआ।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुविधाओं के लिए होगी बैठक

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए विधान परिषद के सभापति राम शिंदे की अध्यक्षता में विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सीधे एयरपोर्ट परिसर में ही होगी, ताकि जमीनी हालात का आकलन कर आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।

विधान परिषद में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने स्वीकार किया कि यात्रियों को नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने में फिलहाल असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि मेट्रो समेत अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को राहत मिलेगी।

29 मार्च से 74 घरेलू उड़ानें शुरू

मंत्री ने जानकारी दी कि 29 मार्च 2026 से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 74 घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इनमें कोल्हापुर और छत्रपति संभाजीनगर के लिए उड़ानें भी शामिल होंगी। इसके अलावा नागपुर-नवी मुंबई विमान सेवा पहले से संचालित है, जिससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

आपदा में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेगा विशेष सिस्टम

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार विशेष ट्रैकिंग और इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम विकसित करेगी। विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने भाजपा सदस्य प्रशांत बंब के प्रश्न के जवाब में कहा कि संवेदनशील वर्गों, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। इस सिस्टम के जरिए उनकी लोकेशन, स्वास्थ्य स्थिति और जरूरतों की जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उन्हें त्वरित चिकित्सा सहायता मिल पाएगी।

आपदा प्रबंधन में बेहतर समन्वय पर जोर

मंत्री ने बताया कि भारी बारिश या बाढ़ की स्थिति बनते ही स्वास्थ्य विभाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। पिछली बाढ़ के दौरान धाराशिव सहित कई प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों ने बेहतर समन्वय के साथ काम किया था। भविष्य में आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से राहत और चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जा सकें।

संपत्ति कर वसूली कम होने पर 9 कर्मचारी निलंबित

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

महानगर पालिका में संपत्ति कर वसूली अपेक्षा से कम रहने के कारण आयुक्त अनमोल सागर के आदेश पर 9 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई को प्रशासन ने वसूली में लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम बताया है। इस निलंबन के खिलाफ 'महाराष्ट्र राज्य जनरल मजदूर कामगार यूनियन' ने कड़ा विरोध जताया है। यूनियन अध्यक्ष भानुदास भसाले और सेक्रेटरी श्रीपत तांबे सहित अन्य पदाधिकारियों ने इसे मनपा प्रशासन का मनमाना निर्णय बताया है।

यूनियनों ने आयुक्त को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर मुरलीधर पाटिल, अनिरुद्ध वाणी, वसंत भोईर, प्रमोद जाधव, धर्मेंद्र शेलार, आनंद जगताप, मिलिंद म्हात्रे, सुरेंद्र साल्वी और शेखर जाधव के निलंबन का विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि ये कर्मचारी पिछले 10-12 वर्षों से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

अभय योजना के बावजूद नहीं बढ़ी वसूली

मनपा में टैक्स वसूली की स्थिति लंबे समय से चिंताजनक बनी हुई है। बार-बार लागू की गई 'अभय योजना' के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है और ब्याज माफी के चलते करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। इस पर विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

छुट्टी पर कर्मचारी भी निलंबित, प्रक्रिया पर सवाल

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक छुट्टी पर चल रहे लिपिक को भी निलंबित कर दिया गया। साथ ही हाल ही में पदोन्नत एक अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई। यूनियन का आरोप है कि बिना कारण बताओ नोटिस और उचित जांच के इस तरह की कार्रवाई नियमों के खिलाफ है। कई कर्मचारियों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे ईमानदारी से काम करने वालों का मनोबल गिर रहा है। यूनियनों ने मांग की है कि मनपा प्रशासन केवल कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी भी तय करे और टैक्स विभाग में पारदर्शिता व कुशल नेतृत्व सुनिश्चित किया जाए।

कई इलाकों में शुक्रवार को पानी रहेगा बंद

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

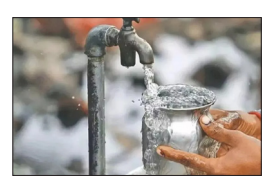

ठाणे मनपा क्षेत्र में एमएमआरडीए द्वारा आनंद नगर से साकेत तक एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य के दौरान पानी की मुख्य पाइपलाइन प्रभावित हो रही है। इसी के तहत 813 मिमी व्यास की पुरानी पाइपलाइन को हटाकर 900 मिमी व्यास की नई पाइपलाइन जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की जाएगी।

मनपा के अनुसार, यह कार्य शुक्रवार 27 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू होकर शनिवार 28 मार्च सुबह 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान कुल 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इसके बाद भी 1 से 2 दिनों तक कम दबाव से पानी मिलने की संभावना जताई गई है।

इन इलाकों में पूरी तरह बंद रहेगी सप्लाई

इस अवधि में इंदिरानगर, साठेनगर, अंबेवाड़ी, दवले नगर, सावरकर नगर, लोकमान्य नगर (पाडा क्रमांक 2, 3, 4), चैतीनगर, परेरानगर, झंजेनगर, श्रीनगर, किसान नगर, शिवटेकड़ी, शांतिनगर, कैलासनगर, भटवाड़ी, वारलीपाड़ा, रूपादेवी पाडा, रामनगर, सी.पी. तलाव और येऊर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस दौरान पानी का संयमित उपयोग करें और प्रशासन का सहयोग करें।

शहीद दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय में अमर क्रांतिकारियों को किया गया नमन

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

शहीद दिवस के गरिमामयी अवसर पर ठाणे जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अभिवादन समारोह में अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल और निवासी उप जिलाधिकारी डॉ. संदीप माने सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को याद किया।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सरजेराव मस्के-पाटिल, शशिकांत गायकवाड़, वरुणकुमार सहारे, वैशाली माने और तहसीलदार सचिन चौधरी सहित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के निदेशक घनश्याम मेहता व अन्य अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कामगारों के काम के घंटे बढ़ाने वाला विधेयक वापस

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

सरकार करेगी नियमों का पुनरीक्षण

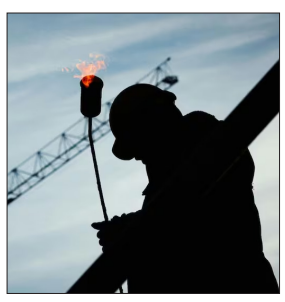

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के दैनिक कार्य घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 करने के अपने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को सोमवार को वापस ले लिया है। श्रम विभाग के सूत्रों के अनुसार, विधेयक के प्रावधानों में स्पष्टता की कमी और विभिन्न क्षेत्रों से मिली तीखी प्रतिक्रियाओं के कारण यह कदम उठाया गया है। प्रस्तावित कानून में काम के घंटों के साथ-साथ 'स्प्रेड-ओवर' (कार्यकाल विस्तार) को 12 घंटे करने और बिना विश्राम के लगातार 6 घंटे काम करने की अनुमति जैसे प्रावधान शामिल थे। कामगार संगठनों ने इन बदलावों पर चिंता जताते हुए कहा था कि इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पंजीकरण नियमों और तकनीकी पहलुओं पर फंसा पेंच

विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी था कि 20 से कम कर्मचारियों वाले छोटे प्रतिष्ठानों को 'पंजीकरण प्रमाण पत्र' की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल व्यवसाय की जानकारी सरकार को देनी होगी। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों पर प्रशासनिक बोझ कम करना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना था। हालांकि, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि बिना पंजीकरण के कामगारों के अधिकारों का संरक्षण कैसे सुनिश्चित होगा। श्रम विभाग के एक उच्चाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब सभी तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं का गहन अध्ययन करने के बाद ही आवश्यक सुधारों के साथ यह विधेयक दोबारा सदन में पेश किया जाएगा।

क्रूज ड्रग्स रिश्वत मामला

समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत नहीं मांगने का किया दावा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सोमवार को क्रूज ड्रग्स केस में रिश्वत मांगने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत नहीं मांगने का दावा किया। वानखेड़े के वकील ने कहा कि आर्यन खान केस में कुछ प्राइवेट लोगों पर रिश्वत लेने का आरोप है और उनका एनसीबी के पूर्व अधिकारी से कोई लेना-देना नहीं है। 24 मार्च को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ के समक्ष रशीद खान पठान की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से क्रूज ड्रग्स केस में रिश्वत मांगने के मामले में समीर वानखेडे और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान वानखेड़े की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने दावा किया कि उनकी तरफ से रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई थी। उन्हें कोई पैसा नहीं मिला और ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी ने उन्हें पैसे दिए हों। कुछ प्राइवेट लोगों पर पैसे लेने का आरोप है और उनका वानखेड़े से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी और के पैसे लेने का है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से ठोस सबूत दिखाने को कहा था। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। आरोप है कि एनसीबी की ओर से आर्यन को छोड़ने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। सीबीआई ने एक स्पेशल इन्क्वायरी टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस टीम का गठन एनसीबी अधिकारियों कथित तौर पर प्रक्रिया में हुई चूकों की जांच के लिए किया गया था।

पीएम ई-बस सेवा में छोटे शहरों को शामिल करने की मांग

डीबीडी संवाददाता । मुंबई/नई दिल्ली

राज्यसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चव्हाण ने 'पीएम ई-बस सेवा' योजना के तहत महाराष्ट्र के टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए अधिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस योजना का विस्तार छोटे शहरों तक होना जरूरी है, क्योंकि वहां वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते सार्वजनिक परिवहन सेवाएं विकसित करने में कठिनाई आती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब में कहा कि सरकार इस योजना के अगले चरण में अधिक से अधिक शहरों को शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, दूसरे फेज के लिए अंतिम मानदंड अभी तय नहीं किए गए हैं, लेकिन 35,000 इलेक्ट्रिक बसों के वितरण की योजना से देशभर में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

CHANGE OF NAME

I,SONI KAUR (also know as SONI JAGDISH SINGH and AYESHA AZEEM), daughter of SHRI SARBAN SINGH SADA SINGH, holder of INDIAN passport no. H5589404 (old passport issued on 26/10/2009) and M9774787 (subsequently issued at DUBAI ,UAE on 07/10/2015) and INDIAN ADHAR CARD NUMBER [730744677596],DO here by declare that I am permanent resident of House No.36, Village Balongi SAS Nagar, Mohali Punjab,140301 India, currently residing Dubai at Villa No.21,9A Street, Muhaisnah 3,DUBAI UAE.
I here by change my name from SONI KAUR to AYESHA AZEEM JAWAID with immediate effect.
Henceforth, I shall be know as AYESHA AZEEM JAWAID for all purposes.
All the above names refer to one and the same person.

दूध माफिया की अब खैर नहीं...

अंधेरी मिलावटी दूध मामले में आरोपियों पर होगी मकोका के तहत कार्रवाई

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

अंधेरी और वर्सोवा इलाके में दूध मिलावट के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को विधानसभा में अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवल ने घोषणा की कि इस मामले के आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वर्सोवा पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने अंधेरी के अलग-अलग 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस ऑपरेशन में दूध में मिलावट करने का पूरा कारखाना पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल, उपकरण और भारी मात्रा में दूषित दूध ज़ब्त किया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है।

मिलावट माफिया' का नेटवर्क

जांच में सामने आया है कि ये आरोपी नामी ब्रांड के दूध के पैकेट काटकर उसमें गंदा पानी और हानिकारक पाउडर मिलाते थे और फिर उसे दोबारा सील कर बाज़ार में बेच देते थे। भाई जगताप ने सदन में कहा कि यह एक बड़ा सिंडिकेट है जो शहर के कोने-कोने में फैला हुआ है, जिसे जड़ से उखाड़ना अब अनिवार्य हो गया है। मंत्री झिरवल ने आश्वासन दिया कि राज्य भर में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंधेरी का यह मामला एक उदाहरण बनेगा ताकि राज्य के अन्य हिस्सों में सक्रिय मिलावटखोरों में कानून का खौफ पैदा हो सके।

मकोका ही क्यों?

विधानसभा में चर्चा के दौरान शिवसेना (ठाकरे गुट) के अनिल परब ने पुरज़ोर मांग की कि इन आरोपियों पर मकोका लगाया जाए। मकोका यानी 'महाराष्ट्र ऑर्गनाइज़्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट' लगने के बाद अपराधियों को कम से कम 6 महीने तक जमानत मिलना नामुमकिन हो जाता है। सरकार का मानना है कि यह केवल मिलावट नहीं, बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला एक संगठित अपराध है।

दूध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी विधायक मनीषा कायंदे, कांग्रेस के भाई जगताप और अन्य विधायकों ने सरकार को घेरा। विधायकों का कहना था कि मिलावटखोरों की पूरी 'सप्लाई चेन' को तोड़ना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में कोई बच्चों और आम जनता की सेहत के साथ सौदा न कर सके। मंत्री झिरवल ने इन सभी मांगों को स्वीकार करते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।

रेहड़ी वालों और सहायकों की होगी नागरिकता जांच

अवैध बांग्लादेशी पाए जाने पर होगा सीधा डिपोर्टेशन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई की सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की पीठ ने बीएमसी और मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वे शहर के सभी रेहड़ी-पटरी वालों और उनके सहायकों की नागरिकता और वैधता की गहन जांच करें। अदालत ने बीएमसी और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे केवल यह न देखें कि रेहड़ी वाला कौन है, बल्कि यह भी जांचें कि उसके साथ काम करने वाला 'सहायक' कौन है। कोर्ट में यह मुद्दा उठा कि कई जगहों पर अवैध प्रवासी (कथित रूप से बांग्लादेशी) सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। अगर कोई भी गैर-भारतीय नागरिक अवैध रूप से रेहड़ी लगाते पाया गया, तो उसे कानून के तहत उसके देश वापस (प्रत्यर्पण) भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

99,000 योग्य हॉकर ही लगा पाएंगे स्टॉल

हाईकोर्ट ने जानकारी दी कि अब तक सर्वे में लगभग 99,000 रेहड़ी-पटरी वाले ही नियमों के अनुसार योग्य पाए गए हैं। कोर्ट का आदेश है कि केवल इन पात्र लोगों को ही तय दिशानिर्देशों के तहत स्टॉल लगाने की अनुमति मिले। इनके अलावा जो भी सड़कों या फुटपाथों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हें 'अवैध' मानकर तुरंत हटाया जाए।

पैदल यात्रियों का रास्ता साफ हो

याचिकाओं में यह मुद्दा उठाया गया था कि रेहड़ी वालों के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैफिक जाम लगता है। कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह सभी स्थायी और अस्थायी स्टॉल का निरीक्षण करे और सुनिश्चित करे कि कोई भी स्टॉल राहगीरों या वाहनों के मार्ग में बाधा न बने।

जीरो टॉलरेंस और पुलिस की जिम्मेदारी

कोर्ट ने पुलिस विभाग को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। केवल बीएमसी की कार्रवाई काफी नहीं है; स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार हटाए गए अवैध हॉकर दोबारा उसी जगह पर कब्जा न कर सकें। पहचान पत्र (ID Card) की जांच अब अनिवार्य हिस्सा होगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि यह केवल अतिक्रमण का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से भी जुड़ा है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ 'फॉरेनर्स एक्ट' के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग को भी सक्रिय रहने के संकेत दिए गए हैं।

सतारा जिला परिषद चुनाव

एकनाथ शिंदे ने पुलिस एक्शन को बताया लोकतंत्र की हत्या

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

सतारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव ने महाराष्ट्र की महायुति (BJP, शिवसेना-शिंदे, और NCP-अजीत पवार) सरकार के भीतर एक बड़ा राजनैतिक संकट खड़ा कर दिया है। पिछले शुक्रवार को हुए इस चुनाव में भाजपा की प्रिया शिंदे ने जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के पीछे के नाटकीय घटनाक्रम ने सहयोगियों के बीच कड़वाहट पैदा कर दी है।

सतारा जिला परिषद की कुल 65 सीटों में से भाजपा के पास 28 सीटें थीं, जबकि बहुमत के लिए 33 की जरूरत थी। शिवसेना (15) और NCP (20) का गठबंधन 35 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में था। लेकिन चुनाव के दिन भाजपा की प्रिया शिंदे को 32 वोट मिले और वे अध्यक्ष चुन ली गईं। विपक्ष (शिवसेना-NCP) का आरोप है कि भाजपा ने पुलिस की मदद से उनके सदस्यों को वोट डालने से रोका और क्रॉस-वोटिंग कराई।

पुलिस कार्रवाई पर भड़के एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने एक निर्वाचित सदस्य को 5-10 साल पुराने केस में वोटिंग से ठीक पहले उठा लिया। शिंदे ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' करार देते हुए कहा कि उन्होंने खुद एसपी को फोन किया था, फिर भी पुलिस ने ₹अपराधियों₹ जैसा व्यवहार किया।

मंत्रियों के साथ 'बदसलूकी' का आरोप

सतारा के पालक मंत्री शंभूराज देसाई (शिवसेना) और मकरंद पाटिल (NCP) ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की की। शंभूराज देसाई के हाथ में चोट भी आई और वे पट्टी बांधे नजर आए। उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कैबिनेट में मुद्दा उठाने की बात कही है।

एसपी तुषार दोशी के निलंबन का निर्देश

इस हंगामे के बाद विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे ने गंभीर रुख अपनाते हुए सतारा के एसपी तुषार दोशी को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है। सरकार से इस मामले में जवाब माँगा गया है कि आखिर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में तनाव को देखते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई और चुनाव के दौरान हुई घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी।

नीलम गोरहे को पद से हटाने की मांग

ठाकरे गुट ने लिखा सभापति को पत्र

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

सातारा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विधान मंडल तक पहुंच गया है। शिवसेना (ठाकरे गुट) ने विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। इस संबंध में सभापति राम शिंदे को पत्र भी भेजा गया है।

ठाकरे गुट ने गोरहे पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विवाद उस समय बढ़ा जब मंत्री शंभूराज देसाई ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि वे इस घटना में घायल हुए। इसके बाद उपसभापति गोरहे द्वारा सातारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या उपसभापति को इस तरह का अधिकार है।

विधान परिषद में प्रस्ताव लाने की तैयारी

शिवसेना (ठाकरे गुट) ने इस मामले को लेकर विधान परिषद में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को गोरहे के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ने के संकेत हैं और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है।

लड़कियों से मारपीट पर भड़की शिवसेना

निरुपम ने कुरार थाने का किया घेराव

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मलाड स्थित कुरार इलाके में हिंदू लड़कियों के साथ कथित मारपीट का मामला अब राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद में बदल गया है। 20 मार्च को हुई इस घटना के विरोध में 23 मार्च को शिवसेना नेता संजय निरुपम ने समर्थकों और पीड़ितों के साथ कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम युवकों ने लड़कियों पर हमला किया।

प्रदर्शन के दौरान निरुपम ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक नहीं लगाई गई, तो समाज में आक्रोश बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कुरार पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते

हुए निरुपम ने तीखे बयान दिए, जिससे माहौल और गर्मा गया। उन्होंने इलाके में पहले हुई घटनाओं का भी जिक्र करते हुए पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए।

हमले में घायल पीड़िता किंजल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उस पर और उसकी दो बहनों पर अचानक हमला किया गया। उसने बताया कि स्थानीय दुकानदारों के हस्तक्षेप से उनकी जान बच सकी। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

महाराष्ट्र को मिलेंगी 1737 नई एम्बुलेंस

मुंबई। महाराष्ट्र में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विधानसभा में बताया कि राज्य में जल्द ही 1,737 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की पहुंच और बेहतर होगी।

सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं में गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र मरीजों को मुफ्त इलाज देना निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में पहले से संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा को और मजबूत करने की योजना बनाई गई है। बढ़ती आबादी और मरीजों की जरूरतों को देखते हुए इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि आपातकालीन स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके।

एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार के लिए एक विशेष जांच समिति गठित की गई है। यह समिति मौजूदा कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देगी। साथ ही निजी एजेंसियों द्वारा संचालित सेवाओं में नियमों के पालन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।

नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली एजेंसियों के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है। यदि किसी एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन या अनियमितता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मध्य रेल
खुली ई–निविदा सूचना
निविदा संख्या EMU/MTN/TM/ Heritage-Gallery/18/ 01-26
माटुंगा कार्यशाला में हेरिटेज गैलरी का विकास और ट्रैक्शन मोटर सेक्शन के कार्यक्षेत्र का नवीनीकरण मात्राः क्षेत्रफलः लगभगः 632 वर्ग मी.। उप मुख्य विद्युत अभियंता (ईएमयू), तीसरी मंजिल, नया प्रशासनिक भवन, कैरिज वर्कशॉप, सेंट्रल रेलवे, माटुंगा, मुंबई–400019, माटुंगा वर्कशॉप में हेरिटेज गैलरी के विकास और ट्रैक्शन मोटर सेक्शन के कार्यक्षेत्र के नवीनीकरण के कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित करता है। कार्य का अनुमानित क्षेत्रफल 632 वर्ग मीटर है। **अनुमानित लागतः** रु. 46,73,709.97, **ईएमडीः** 93,500/-, **निविदा दस्तावेज की लागतः** शून्य, **पूर्णता अवधिः** 6 माह, **निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः** 17.04.2026 को दोपहर 03:00 बजे तक है। निविदा केवल वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से ई–निविदा प्रारूप में ही स्वीकार की जाएगी। निविदा दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध है। **DE-1004**
सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

मध्य रेल
अधिसूचना
Sub: एलटीटी स्टेशन स्थित टीटीई विश्राम गृह के सामान्य रखरखाव एवं प्रबंधक हेतु निविदा, साथ ही रियायती भोजन एवं अन्य वस्तुओं की व्यवस्था, दो वर्ष (731 दिनों) की अवधि के लिए। मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), मध्य रेलवे, प्रथम तल, आरक्षण भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई–400001, भारत के राष्ट्र की ओर से GeM पोर्टल के माध्यम से "एलटीटी स्थित टीटीई विश्राम गृह के सामान्य रखरखाव एवं प्रबंधन, साथ ही रियायती भोजन एवं अन्य वस्तुओं की व्यवस्था, दो वर्ष (731 दिनों) की अवधि के लिए" हेतु निविदा आमंत्रित करते हैं। **ओपन टेंडर GeM बोली संख्याः** GEM/2026/B/7358856, **कार्य का नामः** एलटीटी स्थित टीटीई विश्राम गृह का सामान्य रखरखाव एवं प्रबंधन, साथ ही रियायती भोजन एवं अन्य वस्तुओं की व्यवस्था, दो वर्ष (731 दिनों) की अवधि के लिए। **कार्यालय का पताः** डीआरएम कार्यालय, वाणिज्य शाखा, मुंबई मंडल, **कार्य स्थलः** एलटीटी स्टेशन, मुंबई मंडल, **विज्ञापित मूल्यः** रु. 1,01,43,325.45, **ईएमडी राशिः** रु. 2,00,720/-, **निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः** 04.04.2026 को 21:00 बजे, **अनुबंध की अवधिः** दो वर्ष (731 दिन), **प्रस्तावों की वैधताः** 90 दिन, **Tender Document available on website: https://gem.gov.in/** **DE-1011**
सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

पाखंडी खरात मामला

संबंधित मंत्रियों व अधिकारियों पर हो कार्रवाई: वडेट्टीवार

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने नाशिक के कथित पाखंडी बाबा अशोक खरात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में पाखंड को बढ़ावा मिलना चिंताजनक है और इससे राज्य की छवि प्रभावित हो रही है।

वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि अशोक खरात खुद को भगवान का अवतार बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि खरात के 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं और उस पर महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से समाज में गलत संदेश जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ बड़े अधिकारी और मंत्री भी आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर तीन वरिष्ठ अधिकारी एक होटल में बैठक कर कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी भी गिरफ्तारी टालने में लगे थे। वडेट्टीवार ने इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

सिर्फ एसआईटी नहीं, सख्त कदम जरूरी

वडेट्टीवार ने कहा कि केवल एसआईटी गठन से यह मामला हल नहीं होगा। उन्होंने संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे और अधिकारियों के निलंबन की मांग की। साथ ही, सभी संदिग्धों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कराने पर जोर दिया, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।

उन्होंने मांग की कि बाबा को संरक्षण देने वाले मंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी सह-आरोपी बनाया जाए। वडेट्टीवार ने कहा कि जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, उन्हें इस तरह के मामलों में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी जनता का विश्वास कायम रहेगा।

कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने नाशिक के कथित पाखंडी बाबा अशोक खरात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते

हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में पाखंड को बढ़ावा मिलना चिंताजनक है और इससे राज्य की छवि प्रभावित हो रही है।

'ज्योतिष के नाम पर गुमराह, यौन शोषण के आरोप'

वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि अशोक खरात खुद को भगवान का अवतार बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि खरात के 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं और उस पर महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से समाज में गलत संदेश जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ बड़े अधिकारी और मंत्री भी आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर तीन वरिष्ठ अधिकारी एक होटल में बैठक कर कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी भी गिरफ्तारी टालने में लगे थे। वडेट्टीवार ने इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

SIT से नहीं होगा हल, इस्तीफे और CDR जांच की मांग

वडेट्टीवार ने कहा कि केवल एसआईटी गठन से यह मामला हल नहीं होगा। उन्होंने संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे और अधिकारियों के निलंबन की मांग की। साथ ही, सभी संदिग्धों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कराने पर जोर दिया, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। उन्होंने मांग की कि बाबा को संरक्षण देने वाले मंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी सह-आरोपी बनाया जाए। वडेट्टीवार ने कहा कि जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, उन्हें इस तरह के मामलों में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी जनता का विश्वास कायम रहेगा।

पश्चिम रेलवे
फ्यूल टैंक का आवधिक ओवरहॉलिंग (मरम्मत)
उप मुख्य विद्युत अभियंता (वर्क्स), पश्चिम रेलवे, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013 **ई-टेंडर नोटिस संख्या EL/WA/PL/2025-26/45 दिनांक 13.03.2026 आमंत्रित करते हैं। कार्य का नाम एवं स्थानः** स्कोप ऑफ वर्क और शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार पावर कार के फ्यूल टैंक का आवधिक ओवरहॉलिंग। **कार्य की अनुमानित लागतः** 49,37,167.20 **ईएमडी** : 98,800/- **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समयः** 07.04.2026 को 12:00 बजे तक **टेंडर खोलने की तिथि व समयः** 07.04.2026 को 12:30 बजे अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देखें। 1242
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे
विभिन्न कार्य
वरिष्ठ मंडल अभियंता (दक्षिण), मुंबई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे क्रमांक 1: **ई-टेंडर नोटिस संख्या BCT/25-26/345, दिनांक 18.03.2026 आमंत्रित करते हैं। कार्यः चर्चगेट–विरार सेक्शन में विले पार्ले, खार रोड, सांताक्रूज और बांद्रा स्टेशनों पर 15 कोच ईएमयू के लिए प्लेटफॉर्म बढ़ाने का कार्य (अप और डाउन स्लो लाइन)। अनुमानित लागतः** 70,72,378.90 **ईएमडीः** 1,41,500/- क्रमांक 2: ई-टेंडर नोटिस संख्या BCT/25-26/351, दिनांक 18.03.2026। कार्यः चर्चगेट–विरार सेक्शन में ट्रैक से मलबा, कचरा, प्लास्टिक, कागज आदि हटाने और निपटान का कार्य (ADEN (T/S) PL सेक्शन)। **अनुमानित लागतः** 1,17,15,686.80 **ईएमडीः** 2,08,600/- दोनों टेंडर के लिएः **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः** 14.04.2026 को 15:00 बजे तक टेंडर खोलने की तिथिः 14.04.2026 को 15:30 बजे अधिक जानकारी के लिए **www.ireps.gov.in** देखें। 1247
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

संपादकीय

'शक्ति' संतुलन

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लंबे समय से एक अधूरा वादा रही है। "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" को 2023 में पारित किए जाने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार शीघ्र मिलेगा, लेकिन इसे नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ देने के कारण इसकी समयसीमा अनिश्चित हो गई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा इस कानून में संशोधन कर 2011 की जनगणना के आधार पर ही इसे लागू करने की तैयारी, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कदम के रूप में सामने आ रही है। यदि यह पहल सफल होती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता खुल सकता है। सरकार की यह रणनीति राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है और प्रशासनिक दृष्टि से भी। नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया में समय लगता, जिससे महिला आरक्षण का मुद्दा फिर टल सकता था। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर इसे लागू करना एक तरह से उस 'विलंब की राजनीति' को समाप्त करने का प्रयास है, जिसने दशकों से इस मुद्दे को उलझाए रखा। हालांकि, यह सवाल भी उठता है कि क्या 15 वर्ष पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करना वर्तमान जनसंख्या संरचना के साथ न्याय कर पाएगा। लेकिन सरकार का तर्क है कि इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या असंतुलन को लेकर संभावित विवादों से बचा जा सकेगा, जो हाल के वर्षों में एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने और उनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव अपने आप में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव होगा। इसी तरह राज्यों की विधानसभाओं में भी लगभग 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यह केवल आरक्षण का सवाल नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व के विस्तार का भी संकेत है। अधिक सीटें होने से क्षेत्रीय असंतुलन कम हो सकता है और नए सामाजिक वर्गों को भी राजनीति में जगह मिल सकती है। हालांकि, सीटों में इस तरह की व्यापक वृद्धि से संसदीय कार्यप्रणाली, संसाधनों और प्रशासनिक दक्षता पर क्या असर पड़ेगा, इस पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर प्रारंभिक सहमति दिखाई दे रही है, जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सिद्धांततः इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने विधेयक का विस्तृत स्वरूप देखने और सर्वदलीय चर्चा की मांग की है। यह मांग उचित भी है, क्योंकि इतना बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव बिना व्यापक सहमति के लागू करना भविष्य में विवादों को जन्म दे सकता है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि ऐसे मुद्दों पर पारदर्शिता और संवाद बना रहे। महिला आरक्षण का प्रश्न केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता का भी प्रश्न है। भारत में महिलाएं आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है। आरक्षण के माध्यम से उन्हें राजनीतिक मंच पर लाना, नीतियों और निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, और समाज में उनकी स्थिति को सशक्त बनाना—ये सभी इस पहल के व्यापक उद्देश्य हैं।

डिजिटल युग की नई चुनौती और वैश्विक रुझान

अमित ब्रिज
कार्यकारी संपादक

> वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्मार्टफोन छात्रों की एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उभरा है। यूनेस्को की रिपोर्ट में इस बात का विशेष उल्लेख है कि किसी छात्र के पास केवल फोन की मौजूदगी ही उसके सीखने की क्षमता को कम कर देती है। आंकड़े बताते हैं कि यदि किसी कक्षा में छात्र का ध्यान एक बार फोन के नोटिफिकेशन की ओर जाता है, तो उसे वापस उसी गहन मानसिक स्थिति (Deep Work) में आने के लिए औसतन 20 मिनट का समय लगता है। भारत में, जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव और पाठ्यक्रम की सघनता बहुत अधिक है, वहां यह '20 मिनट का व्यवधान' एक छात्र के पूरे शैक्षणिक सत्र के प्रदर्शन को खराब कर सकता है।

सूचना क्रांति के इस दौर में स्मार्टफोन हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन शिक्षा के मंदिर यानी स्कूलों में इसकी उपस्थिति अब एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में आई यूनेस्को की 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट' ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं का ध्यान इस ओर खींचा है कि तकनीक जहाँ ज्ञान का विस्तार करती है, वहीं इसका अनियंत्रित उपयोग सीखने की प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन रहा है। रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के लगभग 58% देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम केवल एक प्रशासनिक अनुशासन नहीं है, बल्कि उस गिरती एकाग्रता को बचाने की एक वैश्विक कोशिश है जो छात्रों के भविष्य की नींव होती है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी बसती है, यह आंकड़ा एक स्पष्ट चेतावनी है कि हमें तकनीक और शिक्षा के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी।

वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्मार्टफोन छात्रों की एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उभरा है। यूनेस्को की रिपोर्ट में इस बात का विशेष उल्लेख है कि किसी छात्र के पास केवल फोन की मौजूदगी ही उसके सीखने की क्षमता को कम कर देती है। आंकड़े बताते हैं कि यदि किसी कक्षा में छात्र का ध्यान एक बार फोन के नोटिफिकेशन की ओर जाता है, तो उसे वापस उसी गहन मानसिक स्थिति (Deep Work) में आने के लिए औसतन 20 मिनट का समय लगता है। भारत में, जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव और पाठ्यक्रम की सघनता बहुत अधिक है, वहां यह '20 मिनट का व्यवधान' एक छात्र के पूरे शैक्षणिक सत्र के प्रदर्शन को खराब कर सकता है। जिन स्कूलों ने मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, वहां छात्रों के ग्रेड्स में औसतन 6% से 7% तक का सुधार देखा गया है, जो यह साबित करता है कि शांत और विकर्षण-मुक्त वातावरण ही वास्तविक शिक्षा की पहली शर्त है। स्मार्टफोन केवल पढ़ाई में बाधा नहीं डाल रहा, बल्कि यह किशोरों के मानसिक और सामाजिक ढांचे को भी खोखला कर रहा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग छात्रों में 'साइबर बुलिंग', 'बॉडी शेमिंग' और 'ईटिंग डिसऑर्डर' जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है। भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह देखा गया है कि स्कूल के खाली समय (ब्रेक) में छात्र अब आपस में खेलने या संवाद करने के बजाय फोन की स्क्रीन में खोए रहते हैं। यह 'डिजिटल आइसोलेशन' या सामाजिक अलगाव उनके व्यक्तित्व विकास को रोक देता है। स्कूल वह स्थान है जहाँ बच्चे सहानुभूति, नेतृत्व और टीम वर्क सीखते हैं। फोन की स्क्रीन छात्रों को एक कृत्रिम दुनिया में कैद कर देती है, जहाँ उनकी खुशी सोशल मीडिया के 'लाइक्स' पर टिकी होती है, जो अंततः गंभीर तनाव और अवसाद का कारण बनती है। भारत में इस समस्या के दो पहलू हैं। एक ओर जहाँ महंगे निजी स्कूलों में स्मार्टफोन का दुरुपयोग बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के बाद से कई सरकारी और मध्यम वर्गीय स्कूलों में स्मार्टफोन ही शिक्षा का एकमात्र साधन बनकर उभरा है। भारत में 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत तकनीक को शिक्षा का आधार बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ सावधानी की आवश्यकता है। समस्या तकनीक के उपयोग में नहीं, बल्कि उसके समय और स्थान में है। यूनेस्को का तर्क है कि तकनीक को शिक्षक का सहायक होना चाहिए, न कि उसका विकल्प। भारत के कई राज्यों में पहले से ही स्कूलों में फोन लाने पर रोक है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केवल नियमों की नहीं, बल्कि माता-पिता और शिक्षकों के बीच एक साझा समझ की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल तकनीक एक उपकरण के रूप में काम करे, न कि छात्र के समय के लुटेरे के रूप में। दुनिया के कई विकसित देशों ने इस खतरे को पहचान कर कड़े कदम उठाए हैं। फ्रांस ने 2018 में ही 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूलों में फोन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। चीन, इटली और हाल ही में ब्रिटेन ने भी इसी दिशा में कानून बनाए हैं। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि प्रतिबंध के बाद स्कूलों में अनुशासनहीनता के मामलों में भारी कमी आई है और छात्रों के बीच वास्तविक संवाद बढ़ा है। भारत को भी इन वैश्विक मॉडलों का अध्ययन करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाओं को बटोरना नहीं, बल्कि मस्तिष्क को अनुशासित करना है। यदि छात्र स्कूल के 6-7 घंटे भी बिना स्क्रीन के नहीं बिता सकता, तो यह 'डिजिटल एडिक्शन' (डिजिटल लत) की श्रेणी में आता है, जिसका उपचार तत्काल आवश्यक है।

हमारी गीता

कायरता को त्याग दो

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप।।

अर्थः हे पार्थ! नपुंसकता (कायरता) को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता। हे परंतप! हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन अपने धर्म से भाग रहा था। मानसिक विकृति से घिरे अर्जुन को भगवान चुभने वाले अत्यंत कड़े शब्दों में उपहास करते हुए कहते हैं— 'यह क्लैब्य तुम्हें शोभा नहीं देता।' भगवान बहुत कठोर शब्दों में अर्जुन को डाँट रहे हैं। क्लैब्य का अर्थ है—नपुंसकता। कायरता और कर्तव्य से पलायन कोई पुरुषार्थ नहीं है। साहस और धैर्य का अभाव ही क्लैब्य है, जो न पुरुषोचित गुण है और न ही स्त्रियों जैसी कोमल भावना। यह ओज और तेज का अभाव है। जिसके सारथी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं, जो पृथा (कुंती) का पुत्र है और जो 'अर्जुन' (अर्जानात् अर्जुन—अर्थात अर्जित करने वाला) है; उसे ऐसी दुर्बलता शोभा नहीं देती। यह दौर्बल्य भी कोई बड़ा नहीं, बल्कि 'क्षुद्र' है, अर्थात जिसे सहजता से दूर किया जा सकता है। मन कभी तुच्छ नहीं होता, वह तो अनेक शक्तियों और भावनाओं से भरा है। तुच्छ तो वह दुर्बलता है जो हमारे मन में बसे विचारों के कारण हमें कमजोर बनाती है। यदि श्रीकृष्ण जैसे मित्र और हितैषी हमारे जीवन में आएं, तो हमारा न्यूनगंड दूर होने में मदद मिलती है। युद्ध के समय शत्रु पर अनुचित दया करना हितकर नहीं है। वैसे ही, हममें से प्रत्येक का अपने कर्तव्य के प्रति असहाय होना ही असल दुर्बलता है। विद्यार्थी, गृहिणी, उद्यमी या किसान—कोई भी हो, यदि वे अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं करते, तो उनका और समाज का विकास रुक जाएगा। 'विधि' (जो करना है) और 'निषेध' (जो नहीं करना है)—ये दोनों ही कर्तव्य के अंग हैं। सड़कों पर सूचनाएं लिखी होती हैं, जैसेः 'थूकना मना है', 'यहाँ वाहन खड़ा न करें', 'स्वच्छता रखें' आदि। परंतु अक्सर देखा जाता है कि जहाँ सूचना लिखी होती है, वहीं उसके विरुद्ध कार्य होता है। धर्म का पालन मनुष्य नहीं करेगा, तो क्या पशु करेंगे? धर्म केवल मनुष्य के लिए ही है।

शख्सियत

कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों

आजाद हिन्द फौज के अमर सेनानी

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अक्षरों में कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों का नाम एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज है, जिन्होंने अपनी वीरता और अदम्य साहस से ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थीं। 24 मार्च 1915 को पंजाब के तरनतारन जिले में जन्मे ढिल्लों केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि अटूट देशभक्ति की एक जीती-जागती मिसाल थे। उनका जीवन अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और निस्वार्थ सेवा का एक ऐसा संगम है, जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देता है।

गुरबख्श सिंह ढिल्लों का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में हुई, जिसके बाद वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वे दक्षिण-पूर्व एशिया में तैनात थे, तब नियति ने उनके लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध के दौरान उन्हें जापानी सेना ने युद्धबंदी बना लिया था, और यहीं से उनके जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। अपनी मातृभूमि को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने का संकल्प उनके भीतर जाग उठा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 'दिल्ली चलो' का नारा दिया और आजाद हिन्द फौज (INA) का पुनर्गठन किया, तब जी. एस. ढिल्लों ने अपनी सुख-सुविधाओं और ब्रिटिश पद का त्याग कर नेताजी का साथ चुना। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें INA की 'नेहरू ब्रिगेड' का कमांडर नियुक्त किया गया। बर्मा के मोर्चे पर उन्होंने जिस बहादुरी से युद्ध लड़ा, वह सैन्य इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। सीमित संसाधनों और बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद, ढिल्लों और उनके साथियों ने ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। वे दृढ़ता से मानते थे कि एक सैनिक के लिए वतन की आजादी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद, कर्नल ढिल्लों को कर्नल प्रेम सहगल और जनरल शाहनवाज खान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन पर 'राजद्रोह' का मुकदमा चलाया, जिसे दुनिया 'लाल किला ट्रायल' के नाम से जानती है। यह मुकदमा भारत की आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पहली बार भारत के तीन अलग-अलग धर्मों के सपूत—एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख—एक ही लक्ष्य के लिए कटघरे में साथ खड़े थे। इस मुकदमे ने पूरे देश में एकता की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ दी। 'सहगल-ढिल्लों-शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज' का नारा हर भारतीय की जुबान पर गूँज उठा। जनसैलाब के भारी दबाव के कारण अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें रिहा कर दिया गया। आजादी मिलने के बाद कर्नल ढिल्लों ने सत्ता या किसी ऊंचे पद की लालसा नहीं की। वे सादगी के साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 'हतोद' गांव में बस गए और खेती-बाड़ी को ही अपना जीवन बना लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन समाज सेवा और साहित्य को समर्पित कर दिया। उनकी लेखनी और संस्मरणों में हमेशा देशप्रेम की महक बनी रही। कर्नल ढिल्लों का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस कार्यों और बलिदान में निहित होती है। उन्होंने सिद्ध किया कि जब लक्ष्य राष्ट्र की सेवा हो, तो जाति और धर्म की दीवारें स्वतः ही ढह जाती हैं। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया। 6 फरवरी 2006 को इस महान नायक ने अंतिम सांस ली। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें उनके जैसे वीरों के संघर्ष को हमेशा नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर दिया।

जीवन ऊर्जा

जॉर्ज एग्रीकोला : जन्म : 24 मार्च 1494

जन्म

समय की कद्र करने वाला ही इतिहास रचता है

जर्मनी के महान वैज्ञानिक और विद्वान जॉर्ज एग्रीकोला का जन्म 24 मार्च 1494 को ग्लाउचाऊ, जर्मनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1555 को 61 वर्ष की आयु में केम्निट्ज़ में हुई थी। वे अपनी कालजयी कृति 'डी रे मेटालिका' के लिए विश्व विख्यात रहे, जिन्हें 'खनिज विज्ञान का जनक' (Father of Mineralogy) माना जाता है और जिनका निधन वैज्ञानिक अन्वेषण के एक प्रारंभिक युग का अंत माना जाता है।

प्रकृति के रहस्यों को केवल आंखों से नहीं बल्कि तर्क की गहराई से समझना चाहिए क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में छिपी संपदा समाज की प्रगति का आधार है और अनुशासन ही अन्वेषण की पहली सीढ़ी है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है और सच्ची विद्वत्ता वही है जो मानवता के काम आए क्योंकि समाज तभी फलता-फूलता है जब विज्ञान और नैतिकता साथ चलते हैं। धातुओं का शोधन केवल तकनीक नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा है और इसी तरह चरित्र का निर्माण भी संघर्ष की भट्ठी में होता है जहाँ सत्य की जीत सुनिश्चित होती है। कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र मार्ग है और जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है वही उसके रहस्यों को प्राप्त कर पाता है क्योंकि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। एकता में ही शक्ति है और समाज का ढांचा आपसी सहयोग पर टिका है जहाँ हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है और विचार ही कार्यों की जननी होते हैं। अनुभवों से सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है और समय की कद्र करने वाला ही इतिहास रचता है क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और अनुकूलन ही अस्तित्व की कुंजी है। जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है और बिना साहस के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि डर प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है और न्यायप्रिय समाज ही दीर्घजीवी होता है जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका नहीं बल्कि जीवन का निर्माण होना चाहिए। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे कार्यों का परिणाम भोगेंगी और निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। शांति और सद्भाव ही विश्व कल्याण का मार्ग हैं और अंततः सत्य की ज्योति ही संपूर्ण जगत को आलोकित करती है जिससे मानवता का मार्ग प्रशस्त होता है।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

मत्स्य अवतार : संकट में धर्म और ज्ञान की रक्षा

भारतीय सनातन परंपरा में भगवान विष्णु के अवतारों का उद्देश्य सदा धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश रहा है। इन्हीं अवतारों में सबसे प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार, जो हमें संकट के समय धैर्य, करुणा और कर्तव्य का संदेश देता है। इस कथा का केंद्र है एक पुण्यात्मा और दयालु राजा सत्यव्रत। एक दिन प्रातःकाल वे कृतमाला नदी में स्नान कर तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी-सी मछली आ गई। राजा ने उसे पुनः जल में छोड़ना चाहा, परंतु मछली ने विनम्र स्वर में कहा कि बड़े जीव उसे खा जाएंगे, अतः उसकी रक्षा की जाए। यह सुनकर सत्यव्रत के हृदय में करुणा जाग उठी और उन्होंने उसे अपने कमंडलु में सुरक्षित रख लिया। परंतु यह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह प्रतिदिन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती गई। कमंडलु से मटका, मटके से सरोवर, सरोवर से नदी और अंततः समुद्र—हर स्थान उसके लिए छोटा पड़ता गया। अंततः राजा को समझ आ गया कि यह कोई दिव्य शक्ति है। तब मछली ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान ने सत्यव्रत को चेताया कि सात दिनों में प्रलय आने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि वे एक नाव में सभी जीवों, अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों सहित बैठ जाएं। प्रलय के समय वे स्वयं उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। समय आने पर भयंकर प्रलय हुआ। चारों ओर जल ही जल फैल गया। उसी समय एक विशाल नाव प्रकट हुई, जिसमें सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ बैठ गए। तभी मत्स्य रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उस नाव को सुरक्षित मार्ग दिखाने लगे। उन्होंने न केवल प्राणियों की रक्षा की, बल्कि सत्यव्रत को आत्मतत्त्व का ज्ञान भी दिया, जिससे वे जीवनमुक्त हो गए। इसी समय एक अन्य संकट भी उत्पन्न हुआ था। हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था, जिससे संसार में अज्ञान और अधर्म फैल गया। तब भगवान ने मत्स्य रूप में उस दैत्य का वध कर वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा को सौंप दिया, जिससे सृष्टि का पुनर्निर्माण संभव हुआ। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। यह सिखाती है कि दया और करुणा से किया गया छोटा-सा कार्य भी महान परिणाम ला सकता है। सत्यव्रत की करुणा ही उन्हें भगवान के साक्षात्कार तक ले गई। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि जब-जब संसार में ज्ञान और धर्म पर संकट आता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। मत्स्य अवतार हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, यदि हम सत्य, धैर्य और करुणा का मार्ग अपनाते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

उत्तर प्रदेश की लगभग 160 विधानसभा सीटों पर निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पार्टी इन सीटों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कमर कस रही है। उन्होंने पहले हमारे समाज के लोगों को नेता लैला (देसी शराब) पिला कर गुमराह करते थे।

-संजय निषाद
अध्यक्ष, निषाद

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। यह पार्टी ही उनके द्वारा बनाई गई है। ऐसे में वे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया है। निर्धारित तिथि को उनके नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी।

-ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री

गृहमंत्री के तौर पर उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, यह समय ही बताएगा। सरकार जिसके भी नेतृत्व में बनेगी, उसमें नीतीश का अनुभव और मार्गदर्शन जरूर रहेगा।

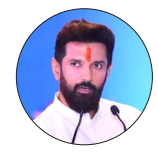

-चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री

अन्ना जी पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पहले भी आंदोलन किए थे। क्या कांग्रेस ने अपने ही खिलाफ उन्हें आंदोलन करने के लिए तैयार किया? मान लीजिए वो आरएसएस और भाजपा द्वारा फंडिड थे, तो महाराष्ट्र में मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई?

-संजय सिंह
नेता, आप पार्टी

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि." के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

भिवंडी। भिवंडी नगर निगम मुख्यालय में 'शहीद दिवस' के अवसर पर देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले अमर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस विशेष कार्यक्रम में महापौर नारायण चौधरी ने तीनों वीर सपूतों की प्रतिमाओं पर पुष्पहार अर्पित कर उनके साहस और राष्ट्रभक्ति को नमन किया और उनके आदर्शों को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। इस अभिवादन समारोह में नगरसेवक संदीप भोईर, अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, उपायुक्त सपना विसावा सहित सहायक आयुक्त शैलेश दोंदे, नितिन पाटिल और अजय महाडिक जैसे वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

डॉ. भावना उल्हास राठोड़ 'संकल्प साहित्य कला मंच' द्वारा सम्मानित

मुंबई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प साहित्य कला मंच द्वारा अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित 'मुद्रा है बैंक्वेट' में श्लोकगीतों में महिला जीवन और उत्सवधर्मिताश विषय पर एक भव्य संगीतमय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में सिद्धार्थ कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय (फोर्ट, मुंबई) के हिंदी विभाग की डॉ. भावना उल्हास राठोड़ को सामाजिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल शुभारंभ संस्था की संयोजिका द्वारा अतिथियों, साहित्य प्रेमियों और प्रतिभागियों के आत्मीय स्वागत के साथ हुआ, जहाँ लोकगीतों के माध्यम से महिला जीवन के विभिन्न आयामों और सांस्कृतिक उल्लास पर चर्चा की गई।

मनपा मुख्यालय में सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी

भिवंडी। भिवंडी महानगर पालिका मुख्यालय के भूतल पर ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के मार्गदर्शन में एक विशेष सूचनात्मक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी जनहितकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए महापौर नारायण चौधरी ने विशेष रूप से 'पिंक रिक्शा' योजना पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के मुख्य रिक्शा स्टैंडों पर बैनर लगाकर कामकाजी महिलाओं तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए।

मुंबई में प्रॉपर्टी प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन

30 लाख नागरिकों को राहत

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई शहर में प्रॉपर्टी से जुड़ी प्रक्रियाओं को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। विधानसभा में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जानकारी दी कि पहली बार प्रॉपर्टी कार्ड की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से शुरू किया गया है, जिससे लाखों नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

नई प्रणाली के तहत अब नागरिक घर बैठे ही प्रॉपर्टी से जुड़े आवेदन कर सकेंगे और उनकी स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी।

इन सेवाओं को किया गया ऑनलाइन

ऑनलाइन की गई सेवाओं में खरीदी-बिक्री (सेल डीड), वारिस प्रक्रिया, गिफ्ट डीड, लीज, मॉर्गेज, रोड सेटबैक, आरक्षण और भूमि अधिग्रहण जैसी प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं। इससे नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सेवाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे नागरिकों को तेज, सुलभ और भरोसेमंद सेवा मिल सकेगी।

तकनीकी अड़चनों का समाधान

मंत्री ने बताया कि पहले मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में अलग-अलग कंप्यूटरीकरण प्रणालियों के कारण तकनीकी समस्याएं आती थीं। नागरिकों की मांग को देखते हुए सरकार ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकसित कर इन समस्याओं को दूर किया है।

मुंबई के 19 राजस्व विभागों और 4 नगर रचना योजनाओं के अंतर्गत आने वाली 27,847 प्रॉपर्टी कार्ड अब आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इससे रिकॉर्ड तक पहुंच और सत्यापन की प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है।

100 मीटर से अधिक ऊंचे पहाड़ों पर विकास से पहले जांच अनिवार्य

मुंबई। राज्य के ऐतिहासिक महत्व वाले पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य अब सख्त नियमों के तहत किए जाएंगे। वन मंत्री गणेश नाईक ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा सदस्य महेश बालदी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील और ऐतिहासिक क्षेत्रों का संरक्षण प्राथमिकता है।

100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों पर अनिवार्य जांच

मंत्री ने बताया कि 100 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के विकास कार्य से पहले विस्तृत जांच और अनुमति लेना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना अनुमति किसी भी व्यावसायिक, आवासीय या अन्य निर्माण गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी।

द्रोणागिरी जैसे क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान

द्रोणागिरी पर्वत जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों का विशेष रूप से संरक्षण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि विकास कार्य स्थानीय नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही किए जाएंगे, ताकि विकास और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।

'जेनरोबोट' का सफल परीक्षण

गटर और मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल संभव

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में नगर निगम (मनपा) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को अशोक नगर इलाके में 'जेनरोबोट' कंपनी की रोबोटिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया। मैनहोल की गहराई और वहां सफाई के दौरान होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के उद्देश्य से आयोजित इस डेमो के दौरान बताया गया कि यह 1 करोड़ 9 लाख रुपये की अत्याधुनिक मशीन संकरी गलियों में भी कुशलता से काम कर सकती है। इस अवसर पर महापौर नारायण चौधरी ने मानव जीवन की सुरक्षा हेतु मशीनी शक्ति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर इस तकनीक को अपनाने पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा; परीक्षण के दौरान एडवोकेट वैभव भोईर, फराज बाहुद्दीन, अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके और उपायुक्त विक्रम दराडे सहित स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

भुसावल मंडल रेल अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू

डीबीडी संवाददाता । भुसावल

मध्य रेलवे के भुसावल मंडल ने मंडल रेल अस्पताल (DRH) में टेलीमेडिसिन सुविधा का औपचारिक शुभारंभ कर डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है, जिसके तहत सभी रेलवे अस्पतालों में टेली-परामर्श सेवाएं शुरू करना अनिवार्य किया गया है।

कर्मचारियों, पेंशनरों और दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

यह सुविधा मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनरों के लिए शुरू की गई है। खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखा गया है, जो दूरस्थ स्टेशनों या बाहरी स्वास्थ्य इकाइयों में रहते हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। टेली-परामर्श के लिए एक समर्पित मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है।

आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ नेटवर्क से जुड़ी सुविधा

टेलीमेडिसिन कक्ष को टेलीविजन और डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जिससे दो-तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव हो सके। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मरीज डॉक्टर से जुड़कर अपनी जांच रिपोर्ट साझा कर सकते हैं और विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

निश्चित समय पर उपलब्ध होगी टेली-परामर्श सेवा

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। टेली-परामर्श मंडल चिकित्सा अधिकारी (DMO) डॉ. जितेश ठाकरे द्वारा किया जाएगा, जबकि आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की टीम भी इसमें शामिल होगी। पूरी प्रक्रिया एक सुरक्षित और संरचित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी।

धूमधाम से मनाया गया बिहार राज्य स्थापना दिवस

मुंबई। महाराष्ट्र लोक भवन में सोमवार को 'बिहार राज्य स्थापना दिवस' का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी का सहयोग रहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार संस्कृति, आध्यात्मिकता और दर्शन की समृद्ध भूमि है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जैसी महान विभूतियां इसी धरती से निकली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बिहार को संसदीय परंपराओं की जन्मभूमि माना जाता है।

देशभर में बिहारी समुदाय का योगदान

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के लोग महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के मूल निवासी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के माध्यम से देश के विकास में भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी बिहारी समुदाय सक्रिय है और वहां भी 'छठ पूजा' जैसे पर्व उत्साह से मनाए जाते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां

इस अवसर पर मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करते हुए लोक नृत्य और भोजपुरी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मिथिला क्षेत्र के लोकनृत्य, जट-जटिन और जजिया जैसे पारंपरिक नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यपाल ने छात्रों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के गीत और नृत्य ऊर्जा और उत्साह से भरपूर हैं। कार्यक्रम के दौरान बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन का संदेश वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया। इस मौके पर रवींद्र कुलकर्णी और अजय भामरे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

'मैन-सिक' जागरूकता कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य पर होगा मंथन

ठाणे। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच ठाणे जिला सूचना एवं प्रसारण कार्यालय और ठाणे मनपा ने संयुक्त रूप से 'मैन-सिकः अवेयरनेस से अवेयरनेस तक' जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करना है।

24 मार्च को होगा कार्यक्रम, सभी के लिए खुला मंच

यह कार्यक्रम मंगलवार, 24 मार्च 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल ऑडिटोरियम, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने नागरिकों, युवाओं और मीडिया प्रतिनिधियों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर संवाद को बढ़ावा मिल सके।

विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन, युवाओं पर रहेगा फोकस

कार्यक्रम में ठाणे प्रादेशिक मनो रोग चिकित्सालय के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. अमोल भुसारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। वे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों, भ्रांतियों और सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे लोगों को सही जानकारी और दिशा मिल सके। 'रेज़ोनेंस कम्युनिकेशंस' द्वारा महाराष्ट्र सरकार के आईईसी ब्यूरो के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष व्यवसाय ठीक चलेगा। पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी। व्यय होगा। प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे। परिश्रम का अनुकूल फल मिलेगा। परिजनों के स्वास्थ्य और सुविधाओं की ओर ध्यान दें।

वृष विवाद से क्लेश होगा। फालतू खर्च होगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। जोखिम न लें। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग हैं। सावधानी व सतर्कता से व्यापारिक अनुबंध करें। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा।

मिथुन बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। जोखिम न उठाएं। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

कर्क मेहनत का फल मिलेगा। योजना फलीभूत होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्ज से दूर रहना चाहिए। खर्च में कमी होगी। कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होने की संभावना है। प्रतिष्ठितजनों से मेल-जोल बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। रोजगार मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ संभव है। जोखिम न लें। धर्म के कार्यों में रुचि आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। मिलनसारिता व धैर्यवान प्रवृत्ति जीवन में आनंद का संचार करेगी। कई दिनों से रुका पैसा मिल सकेगा।

कन्या चोट व रोग से बचें। कानूनी अड़चन दूर होगी। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। क्रय-विक्रय के कार्यों में लाभ होगा। योजनाएं बनेंगी। उच्च और बौद्धिक वर्ग में विशेष सम्मान प्राप्त होगा। भाइयों से अनबन हो सकती है।

तुला कुसंगति से हानि होगी। वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। वाणी परो नियंत्रण रखें, जोखिम न लें। परेशानियों का मुकाबला करके भी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। व्यापारिक लाभ होगा। संतान के प्रति झुकाव बढ़ेगा। शिक्षा व ज्ञान में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें। जायदाद संबंधी समस्या सुलझने के आसार बनेंगे। अनुकूल समाचार मिलेंगे तथा दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे।

धनु किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। लाभ होगा। धन संचय की बात बनेगी। परिवार के कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। रुका कार्य होने से प्रसन्नाता होगी। आर्थिक सलाह उपयोगी रहेगी। कर्ज की चिंता कम होगी।

मकर अति व्यस्तता रहेगी। बुरी खबर मिल सकती है। दौड़धूप अधिक होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। थकान रहेगी। व्यापार-व्यवसाय संतोषप्रद रहेगा। आपसी संबंधों को महत्व दें। अल्प परिश्रम से ही लाभ होने की संभावना है। खर्चों में कमी करने का प्रयास करें।

कुंभ संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। धैर्य एवं शांति से वाद-विवादों से निपट सकेंगे। दुस्साहस न करें। नए विचार, योजना पर चर्चा होगी। स्वयं की प्रतिष्ठा व सम्मान के अनुरूप कार्य हो सकेंगे।

मीन प्रसन्नता रहेगी। संतान की शिक्षा की चिंता समाप्त होगी। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। महत्व के कार्य को समय पर करें। व्यावसायिक श्रेष्ठता का लाभ मिलेगा। मेहनत का फल कम मिलेगा। कार्य की प्रशंसा होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी।

चन्द्र मंगल योग

वैदिक ज्योतिष में चन्द्र मंगल योग की प्रचलित परिभाषा के अनुसार यदि किसी कुंडली में चन्द्रमा तथा मंगल कुंडली के एक ही घर में स्थित हो जाते हैं तो ऐसी कुंडली में चन्द्र मंगल योग का निर्माण हो जाता है। चन्द्र मंगल योग द्वारा प्रदान किये जाने वाले फलों के लेकर विभिन्न ज्योतिषी भिन्न भिन्न मत रखते हैं। कुछ ज्योतिषी यह मानते हैं कि कुंडली में बनने वाला चन्द्र मंगल योग शुभ होता है तथा इस योग के कारण जातक को विभिन्न प्रकार के शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं जबकि कुछ अन्य

प्रियंका जैन
9769994439

ज्योतिषी यह मानते हैं कि कुंडली में बनने वाला चन्द्र मंगल अशुभ होता है तथा इस योग के कारण जातक को विभिन्न प्रकार के अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। आज के इस लेख में हम चन्द्र मंगल योग के कुंडली में निर्माण तथा इस योग के शुभ अशुभ फलों के बारे में चर्चा करेंगे।

चन्द्रमा तथा मंगल के संयोग

कुंडली में चन्द्रमा तथा मंगल के संयोग से बनने वाला चन्द्र मंगल योग जातक को कुंडली में चन्द्रमा तथा मंगल के स्वभाव, बल तथा स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ फल प्रदान कर सकता है। किसी कुंडली में शुभ चन्द्रमा तथा शुभ मंगल का संयोग हो जाने से बनने वाले चन्द्र मंगल योग का परिणाम निश्चिय ही शुभ फलदायी होगा तथा इस प्रकार के चन्द्र मंगल योग के प्रभाव में आने वाले जातक को उसकी कुंडली में चन्द्र तथा मंगल की स्थिति तथा बल के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी कुंडली के पांचवे घर में बनने वाला शुभ चन्द्र मंगल योग जातक को धन, समृद्धि, कलात्मकता आदि जैसे शुभ फल प्रदान कर सकता है जबकि किसी कुंडली के दसवें घर में बनने वाला शुभ चन्द्र मंगल योग जातक को व्यवसायिक सफलता तथा ख्याति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार शुभ चन्द्रमा तथा शुभ मंगल के संयोग से बनने वाला चन्द्र मंगल योग कुंडली के विभिन्न घरो तथा विभिन्न राशियों में अपनी स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ फल प्रदान कर सकता है।

कुंडली में चन्द्रमा तथा मंगल दोनों के अशुभ

दूसरी ओर किसी कुंडली में चन्द्रमा तथा मंगल दोनों के अशुभ होने की स्थिति में इनके संयोग से बनने वाला चन्द्र मंगल योग निश्चय ही अशुभ फलदायी तथा अमंगलकारी होता है जो जातक को उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कष्ट दे सकता है जिनका निर्णय कुंडली में इस प्रकार के अशुभ चन्द्र मंगल योग की स्थिति तथा बल आदि से किया जाता है।

न्यूज़ ब्रीफ

असम विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा का असम में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो सका। झामुमो ने आखिरकार असम विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से जारी सूची के मुताबिक मजबत सीट से प्रीति रेखा बारला, विश्वनाथ से तेहरू गौर, खुमतई से अमित नाग को टिकट मिला है। चाबुआ से भूपेन मुरारी, गोसाईगांव से फेडक्रिसन हांसदा, सोनारी से बलदेव तेली, दुलाजान से पीटर मिंज, रोगोंनादी से पबन सौताल, डिगबोई से भरत नायक चुनाव लड़ेंगे। वहीं भेरगांव से प्रभात दास पनिका, तिंगखौंग से महावीर बास्के, बरचलिया से अब्दुल मजान, रांगापाड़ा से मैथ्यू टोपनो, मरगहटिया से जमाल मिंज, नहरकटिया से संजय बाघ, माकुम से मुन्ना कर्मकार का नाम लिस्ट में हैं। दुमदुमा विधानसभा सीट से रत्नाकर तांती, सारूपाथर से साहिल मुंडा, टीटाबोर से सोनिया, बोकाजन से प्रतापचिंग रंगपहाड़ और खोवांग से प्रभाकर दास का नाम शामिल हैं।

बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 पेपर लीक मामले में डब्लू मुखिया को दबोचा

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2024 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने एक और गिरफ्तारी की है। ईओयू के विशेष छापेमारी दल ने गुप्त सूचना पर पटना के करबिगहिया में छापेमारी कर प्रवीण कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू मुखिया को गिरफ्तार किया है। डब्लू इस कांड के सरगना संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लखीसराय के मानिकपुर थाना अंतर्गत कोनिपार का रहने वाला है।

नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

आजमगढ़। जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में नौकरी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे मुंबई में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया था। साथ ही, उसने शादी करने का भी झांसा दिया, जिसके बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

योगी कैबिनेट में नवयुग पालिका योजना को मिली मंजूरी

यूपी के 58 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पेश, 37 प्रस्तावों को मंजूरी

एजेंसी । लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 37 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 2 प्रस्तावों (प्रस्ताव संख्या 20 और 21) को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु नवयुग पालिका योजना रहा। प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार और संतुलित शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में "नवयुग पालिका योजना" को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 58 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

5 वर्षों में 2916 करोड़ रुपये का निवेश

योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 583.20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी, इस तरह 5 वर्षों (2025-26 से 2029-30) में कुल 2916 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। नवयुग पालिका योजना के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डिजिटल गवर्नेन्स, ई-सेवाओं और तकनीकी समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नागरिक सेवाएं अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेंगी।

किसानों को सौगात

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। बड़ी राहत की बात यह है कि किसानों को अब केवल एमएसपी ही नहीं मिलेगा, बल्कि गेहूं की उतराई, सफाई और छनाई के लिए सरकार की ओर से 20 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसानों के खातों में प्रति कुंतल अधिक राशि भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 30 लाख टन गेहूं खरीद का प्रारंभिक लक्ष्य रखा है।

गोरखपुर बनेगा 'सोलर सिटी': चिलुआताल में लगेगा फ्लोटिंग प्लांट

मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। गोरखपुर के चिलुआताल में 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 80 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। यह प्रोजेक्ट न केवल बिजली की कमी को दूर करेगा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की रैंकिंग भी सुधारेगा। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कानपुर के घाटमपुर में 660 मेगावॉट की तीन इकाइयों वाला पावर प्लांट केंद्र और यूपी सरकार का साझा उपक्रम है। इसकी दो इकाइयां शुरू हो चुकी हैं और तीसरी जल्द शुरू होनी है।

अब नगर पालिकाएं भी बनेंगी 'स्मार्ट'

प्रदेश के 17 नगर निगमों में पहले से ही स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, लेकिन अब सरकार ने नगर पालिकाओं को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का फैसला किया है। नवयुग नगर पालिका योजना के तहत 58 जिला मुख्यालय वाले शहरों को कवर किया जाएगा, जिनमें 55 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस योजना के लिए 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। 1.50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 24 निकायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कोल्ड स्टोरेज की दीवार ढहने से 9 मरे

अमोनिया गैस लीक के कारण हादसा

एजेंसी । प्रयागराज

फाफामऊ क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक कोल्ड स्टोरेज की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे अब तक 9 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना के समय वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए थे। जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चांदपुर के पूर्व विधायक का कोल्ड स्टोरेज बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दीवार गिरने से पहले तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरी दीवार अचानक ढह गई। जानकारी के मुताबिक, हादसे की वजह अमोनिया गैस की पाइप फटना बताई जा रही है।

अमोनिया गैस पाइप फटने से हादसा

पाइप फटने के बाद गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। अमोनिया गैस के रिसाव के कारण आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त करीब 20 मजदूर कोल्ड स्टोर के अंदर काम कर रहे थे।

गुस्साए लोगों ने एंबुलेंस पर पथराव किया

हादसे के बाद जब बचाव टीम और रेस्क्यू टीम पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने एंबुलेंस पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस से तीखी नोक-झोंक भी हुई। अभी तक 9 शव बरामद हुए हैं। जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार और डीएम मनीष वर्मा मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद अफसरों से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। घायलों को स्वरूप रानी अस्पताल (SRN) ले जाया गया है। इनमें से ज्यादातर की हालत नाजुक बताई जा रही है।

5 लाख की घूस लेते बड़ा बाबू और दलाल गिरफ्तार

एजेंसी । सरायकेला

समाहरणालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू-अर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम कुमार आचार्य और दलाल विनय कुमार तिवारी को पांच लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। चांडिल के धुनाबुरू निवासी गुरुचरण सिंह सरदार की शिकायत पर एसीबी ने मामले की जांच की और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर पहले दलाल को पकड़ा, फिर समाहरणालय पहुंचकर प्रीतम को भी दबोच लिया।

मुआवजा दिलाने के नाम पर 40 लाख की डील

जानकारी के अनुसार, धुनाबुरू गांव में पावर ग्रिड निर्माण के लिए गुरुचरण सिंह सरदार को करीब डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा मिलना था। आरोप है कि इस मुआवजे के एवज में प्रीतम ने पहले 60 लाख रुपये घूस मांगी, जो बाद में 40 लाख रुपये में तय हुई। जो बाद में 40 लाख रुपये में तय हुई।

नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं

हर जिले में महीने में दो बार होगी NCORD की बैठक

अवैध कमाई से बनी संपत्ति होगी जब्त

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य को नशे के जाल से पूरी तरह मुक्त करने के लिए एक 'ज़ीरो टॉलरेंस' रोडमैप तैयार किया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की बैठक में तस्करों की कमर तोड़ने और युवाओं को जागरूक करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि नशा उन्मूलन में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हर जिले में महीने में कम से कम दो बार नार्कोटिक्स को-ऑर्डिनेशन की बैठकें अनिवार्य होंगी। जिन जिलों के अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक का मकसद पुलिस, राजस्व और कृषि विभाग के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है। सरकार केवल तस्करों को जेल भेजने तक सीमित नहीं रहेगी।

एएनटीएफ का रिपोर्ट कार्ड

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022 से अब तक लगभग 2,71,802 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है, जिसकी कीमत करीब 925 करोड़ रुपये है। केवल 2026 के शुरुआती महीनों में ही 56 से अधिक मामले दर्ज कर 100 से ज्यादा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। अब पुलिस ने 20 'हाई वैल्यू टारगेट' (बड़े माफिया) की लिस्ट तैयार की है। शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे की बिक्री को रोकने के लिए विशेष हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं।

जफराबाद में 1.18 करोड़ का बॉक्स कल्वर्ट स्वीकृत

एजेंसी । जौनपुर

जौनपुर के जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना को मंजूरी मिली है। ग्राम हरिपुर भड़ेहरी से पाली के बीच नाले पर बॉक्स कल्वर्ट (लघु सेतु) के निर्माण के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में पहुंच मार्ग और अतिरिक्त मार्ग का निर्माण भी शामिल है। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा इस निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह लघु सेतु जफराबाद विधानसभा क्षेत्र को केराकत विधानसभा से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय आवागमन सुगम होगा।

सचिवालय की सुरक्षा होगी हाईटेक

सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के लिए स्थान तय, हर गतिविधि पर रहेगी नजर

एजेंसी । पटना

राज्य सरकार ने सभी सचिवालयों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सचिवालय भवनों व परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के तहत नियंत्रण कक्ष एवं निगरानी केंद्र (व्यूइंग सेंटर) के लिए अलग-अलग स्थान तय कर दिए हैं। गृह विभाग की पहल पर यह कार्य बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रान) के माध्यम से कराया जाएगा। बताया गया है कि इस प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति मिल चुकी है।

बनाए जाएंगे नियंत्रण कक्ष एवं निगरानी केंद्र

सचिवालयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फरवरी माह में ही सीसीटीवी कैमरे लगाने और नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी थी।सूत्रों के अनुसार जिन स्थानों पर नियंत्रण कक्ष एवं निगरानी केंद्र बनाए जाने हैं, उनमें विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन, पुराना सचिवालय और सिंचाई भवन प्रमुख हैं। विश्वेश्वरैया भवन के पार्किंग गार्डन क्षेत्र में एक बड़े कक्ष को नियंत्रण कक्ष के रूप में चिह्नित किया गया है।

सचिवालय में आने-जाने वालों पर रहेगी नजर

वहीं, पुराना सचिवालय परिसर के उत्तरी विंग के भूतल स्थित फ्रंट कॉरिडोर में एक बड़े कक्ष को निगरानी केंद्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इसी प्रकार सिंचाई भवन के नवनिर्मित पार्किंग स्थल के ऊपर स्थित कक्ष को भी इस उद्देश्य के लिए चयनित किया गया है। ताकि पूरे भवन की गतिविधियों पर एक साथ नजर रखी जा सके।

व्यापार जगत

वैश्विक बाजार में बड़ी राहत

ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के बाद टूटा कच्चा तेल

कीमतें 15% तक फिसलीं, $100 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड

एजेंसी । मुंबई

वैश्विक तेल बाजार के लिए सोमवार (23 मार्च 2026) का दिन बड़ी राहत लेकर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टालने के फैसले ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची खलबली को शांत कर दिया है।

होर्मुज संकट: तेल उछला, महंगाई का खतरा

पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (दुनिया का सबसे प्रमुख तेल मार्ग) को लगभग बंद कर दिया था। सप्लाई रुकने के डर से तेल की कीमतें $110-$115 प्रति बैरल तक पहुँच गई थीं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था क्योंकि वैश्विक तेल का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुज़रता है।

भारत जैसे देशों के लिए बड़ी जीत

भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। तेल की कीमतों में 15% की गिरावट का मतलब है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही, माल ढुलाई सस्ती होने से खाने-पीने की चीजों के दाम भी स्थिर हो सकते हैं। बाजार में कीमतों के गिरने का मुख्य कारण 'डी-एस्केलेशन' (तनाव में कमी) है। जब ट्रंप ने हमले टाले, तो निवेशकों को लगा कि अब युद्ध शायद टल जाएगा और होर्मुज का रास्ता फिर से खुल जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाजिर बाजार से 2.52 अरब अमेरिकी डॉलर खरीदे

एजेंसी । मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी 2026 में हाजिर मुद्रा बाजार से शुद्ध 2.526 अरब अमेरिकी डॉलर खरीदे हैं। यह खरीद ऐसे समय में हुई है जब केंद्रीय बैंक ने इससे पहले लगातार सात महीनों तक डॉलर की शुद्ध बिक्री की थी। इससे पहले आरबीआई ने मई 2025 में 1.764 अरब डॉलर की खरीद की थी, जबकि जून से दिसंबर 2025 तक लगातार बिक्री का दौर जारी रहा। दिसंबर में 10 अरब डॉलर से अधिक की बिक्री आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में शुद्ध 10.02 अरब डॉलर की बिक्री हुई थी।

दिसंबर में 10 अरब डॉलर से अधिक की बिक्री

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में शुद्ध 10.02 अरब डॉलर की बिक्री हुई थी। अक्तूबर में 11.877 अरब डॉलर, सितंबर में 7.910 अरब डॉलर, अगस्त में 7.695 अरब डॉलर, जुलाई में 2.540 अरब डॉलर और जून में 3.661 अरब डॉलर बेचे गए थे। वहीं, जनवरी 2026 में सकल आधार पर केंद्रीय बैंक ने 27.999 अरब डॉलर खरीदे और 25.473 अरब डॉलर बेचे। फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा से रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ था।

रुपये पर वैश्विक दबाव, आरबीआई का हस्तक्षेप जारी

लेकिन इसके बाद यह स्थिर बना रहा। मार्च 2026 (20 मार्च तक) में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में बढ़ी अस्थिरता का असर रुपये पर पड़ा और उस पर दबाव देखा गया। ऐसे में रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई समय-समय पर बाजार में हस्तक्षेप करता है, जिसमें डॉलर की खरीद और बिक्री शामिल है।

स्वतंत्र निदेशक बिना सबूत आक्षेप न लगाएं: सेबी

एजेंसी । मुंबई

एचडीएफसी बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के कुछ दिन बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि स्वतंत्र निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम करें और बिना ठोस सबूत के कोई आक्षेप न लगाएं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चक्रवर्ती ने नैतिकता और मूल्यों से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ने से एचडीएफसी बैंक के शेयर में तेज गिरावट।

सोने में फिलहाल तेजी के आसार नहीं

एजेंसी । मुंबई

भारतीय सर्राफा बाजार के लिए पिछला सप्ताह बेहद निराशाजनक रहा, जहां सोने और चांदी की कीमतों में दशकों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और ऊंची ब्याज दरों की आशंका के चलते सोना करीब 1.46 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.45 लाख प्रति किलोग्राम तक फिसल गई। हालांकि, भारी गिरावट के बाद इस सप्ताह कीमतों में हल्की रिकवरी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बड़ी तेजी के आसार फिलहाल कमजोर हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1983 के बाद सबसे बड़ी गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पिछले एक सप्ताह में 11 फीसदी से अधिक टूट चुका है, जो 1983 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही है। फिलहाल इसकी कीमत करीब 4,488 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है और यह लगातार आठवें दिन गिरावट की ओर बढ़ रहा है, जो अक्टूबर 2023 के बाद सबसे लंबा गिरावट का दौर है। इससे पहले जनवरी के अंत में सोना करीब 5,600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा था।

भारतीय बाजार पर असर, आगे सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव संभव

इस वैश्विक गिरावट का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी 32,663 रुपये (12.59%) गिरकर 2.26 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जबकि सोना 13,974 रुपये (8.82%) गिरकर 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर इंडेक्स के 100 के पार जाने, ऊंची ब्याज दरों की आशंका और महंगाई के दबाव के चलते सोने पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में सोना 1.40 लाख से 1.47 लाख प्रति 10 ग्राम के दायरे में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर सकता है। भारतीय सर्राफा बाजार के लिए पिछला हफ्ता बेहद खराब रहा, जहां सोने और चांदी की कीमतों में दशकों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और ऊंचे ब्याज दरों की आशंका के चलते सोने की कीमत 1.46 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.45 लाख प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। पिछले हफ्ते भारी गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह हल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद कम है।

आर्थिक गतिविधि मजबूत रहेगी: आरबीआई

एजेंसी । मुंबई

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अमेरिका द्वारा शुरू की गई नई व्यापार जांच के चलते वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, फरवरी महीने में आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत मिले हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों से निपटने के लिए पर्याप्त है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमान अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाते हैं। बुलेटिन के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई फरवरी में खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ी है।

रोहित जैन बने अस्गार्ड अल्कोबेव के चेयरमैन एमिरिटस

एजेंसी । मुंबई

अस्गार्ड अल्कोबेव लिमिटेड ने अपने बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए श्री रोहित जैन को 21 मार्च 2026 से अगले पांच वर्षों के लिए 'चेयरमैन एमिरिटस और बोर्ड के रणनीतिक सलाहकार' के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी के अनुसार यह कदम भविष्य के विजन और बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रोहित जैन के पास ब्रुअरीज, डिस्टिलरीज के साथ-साथ सीमेंट और स्टील जैसे विभिन्न उद्योगों का अनुभव है। 2007 में स्थापित 'सीएमजे ब्रुअरीज' को उन्होंने क्षेत्रीय खिलाड़ी से राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में मदद की थी। इस अनुभव का लाभ अब अस्गार्ड अल्कोबेव को अपनी नई पहचान स्थापित करने और निवेशकों को लंबी अवधि की स्थिरता का भरोसा देने में मिलेगा। कंपनी ने बताया कि रोहित जैन की भूमिका मुख्यतः सलाहकार की होगी, जिससे बोर्ड संरचना में बदलाव किए बिना उनके ज्ञान और रणनीतिक दृष्टिकोण का लाभ उठाया जा सकेगा। उनके बिजनेस स्केलिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत कुशलता के कौशल से कंपनी अपनी नई ब्रांड पहचान के साथ मार्केट में मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है। हाल ही में रौनक जैन के एमडी नियुक्त होने के बाद यह कदम कंपनी की 'फ्यूचर रेडी' सोच और मैनेजमेंट में अनुशासन की दिशा को दर्शाता है।

आईपीएल काउंटडाउन

केकेआर : नई टीम, नई सोच, नई शुरुआत

- कोलकाता नाइट राइडर्स को नए कोच नायर और बदली बल्लेबाजी से बड़ी उम्मीदें
- अजिंक्य रहाणे को कप्तानी के साथ अपनी बल्लेबाजी का स्तर उठाना होगा

एजेंसी । कोलकाता

एक समय आईपीएल में रणनीति की दिशा तय करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स अब बदलाव के दौर से गुजर रही है। नए कोर, नए कोच और बदली हुई बल्लेबाजी सोच के साथ सवाल यही है-क्या यह टीम 2025 की निराशा भुलाकर फिर से चमक पाएगी ?गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में साल 2024 में चैंपियन बनने वाली यह टीम 2025 में आठवें पायदान पर क्या खिसकी, इसकी चूलें हिल गईं। अब 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने जा रही केकेआर के सामने साख बचाने की चुनौती होगी।

नायर का नया दौर

2024 की जीत गौतम गंभीर के लिए भारतीय मुख्य कोच बनने का टिकट साबित हुई, लेकिन उनके जाते ही टीम की रणनीतिक स्पष्टता कहीं खो गई। इस साल टीम ने अभिषेक नायर को मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी है। नायर को घरेलू खिलाड़ियों की मनोविज्ञान समझने वाला उस्ताद माना जाता है।

अनुभव और आधुनिकता का संगम

टीम की कमान और बल्लेबाजी की धुरी इस बार अजिंक्य रहाणे के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। टी-20 के इस 'पावर-हिटिंग' युग में रहाणे अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी से एक अलग संतुलन पैदा कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अपने खेलने के अंदाज में सूक्ष्म बदलाव किए हैं-परंपरागत शॉट अब वे अपरंपरागत गति (टेंपो) के साथ खेल रहे हैं। फिन एलन और टिम साइफर्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के बीच रहाणे ड्रेसिंग रूम में वह शांति और स्पष्टता ला सकते हैं, जिसकी कमी पिछले सीजन में साफ खली थी।

कैमरन ग्रीन पर नजरें

केकेआर ने इस बार मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाकर सबको चौंका दिया था। ग्रीन की भूमिका इस सीजन में टीम की किस्मत तय करेगी। वे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज गेंदबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग का गुलदस्ता देते हैं। उनके साथ रोवमैन पॉवेल की मौजूदगी निचले क्रम में रिंकू सिंह को वह आजादी देगी, जिससे केकेआर अपने 'फिनिशिंग टच' के लिए जानी जाती है।

स्पिन की 'रहस्यमयी' जोड़ी

जहां बल्लेबाजी में बड़ा फेरबदल हुआ है, वहीं केकेआर ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी स्पिन विभाग में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी आज भी टूर्नामेंट की सबसे घातक जोड़ी मानी जाती है। नरेन के चार ओवर का किफायती कोटा और पावरप्ले में पिंच-हिटर की भूमिका टीम को वह लचीलापन देती है जो किसी और के पास नहीं है। वहीं, चक्रवर्ती बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का पासा पलटने में माहिर हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बाद सर्वाधिक तीन बार खिताब जीतने वाली इकलौती टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने अब वापसी की बड़ी चुनौती है।

'एक्स-फैक्टर' मुजरबानी

घुटने की चोट के कारण हर्षित राणा का बाहर होना केकेआर के लिए बड़ा झटका है। उनकी भरपाई के लिए टीम ने जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को शामिल किया है। मुजरबानी अपनी लंबाई के कारण जिस तरह का उछाल पैदा करते हैं।

ओपनिंग में बदलाव : फिन एलन और रहाणे की जोड़ी आक्रामकता और संयम का अनूठा मिश्रण पेश करेगी।

गेम चेंजर : टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन क्या 'मास्टरस्ट्रोक' साबित होंगे।

रणनीतिक पहचान : कोच अभिषेक नायर के मार्गदर्शन में टीम को अपनी पुरानी रणनीतिक स्पष्टता वापस पानी होगी।

दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी अल्काराज को हरा कोर्डा ने रचा इतिहास

- मियामी ओपन : टूर्नामेंट के तीसरे दौर में ही स्पेन के कार्लोस को बाहर का रास्ता दिखाया
- महिला एकल में मौजूदा चैंपियन सबालेंका का सफर जारी

एजेंसी । मियामी गार्डंस

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज मियामी ओपन के तीसरे दौर में ही हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें रविवार रात खेले गए मुकाबले में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा ने शिकस्त देकर इतिहास भी रच दिया। अब कोर्डा का सामना स्पेन के ही मार्टिन लैंडालुइस से होगा।

तीन सेट में पराजित किया

दुनिया के 36वें नंबर के खिलाड़ी कोर्डा ने तीसरे दौर के मुकाबले में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दो घंटे 19 मिनट तक चले मैच में 22 वर्षीय अल्काराज को 6-3, 5-7, 6-4 से पराजित किया। कोर्डा की सात ग्रैंड स्लैम चैंपियन अल्काराज पर यह दूसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2022 में मोंटे कॉर्लो मास्टर्स के राउंड-32 में उन्हें हराया था।

सिर्फ तीसरा मौका

कोर्डा की जीत 1990 में एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से केवल तीसरा मौका है जब किसी 32वीं वरीय खिलाड़ी ने शीर्ष खिलाड़ी को हराया है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही मुकाबले मियामी में और तीसरे दौर में हुए। सबसे पहले 1998 में वेन फरेरा ने पीट संप्रास को हराया था। फिर राफेल नडाल ने 2004 में रोजर फेडरर के खिलाफ अपने पहले ही मैच में जीत हासिल की थी। इसके अलावा इससे पहले इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में अल्काराज को दानिल मेदवेदेव ने हराया था। दूसरी ओर गैर वरीय खिलाड़ी मार्टिन ने 14वीं वरीयता प्राप्त कारेन खाचानोव को 6-3, 7-6 से शिकस्त दी। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और टॉमी पॉल भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। छठी वरीयता प्राप्त फ्रिट्ज ने रीली ओपेलका को 6-3, 6-4 से हराया जबकि 22वीं रैंकिंग वाले पॉल ने रफाएल कोलिंगनोन को 6-2, 3-6, 7-6 से मात दी।

न्यूज ब्रीफ

न्यूजीलैंड शुरू करेगा फ्रेंचाइजी आधारित एनजेड-20 लीग

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड ने घरेलू और विश्व क्रिकेट के टी-20 प्रारूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फ्रेंचाइजी आधारित एनजेड 20 लीग शुरु करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (एनजेडसी) की हुई बैठक में विचार विमर्श के बाद घरेलू टी-20 प्रारुप के भवष्यि के लिए सुपर स्मैश की जगह एनजेड-20 को पसंदीदा विकल्प चुना है। बोर्ड का मानना है कि इससे घरेलू और युवा क्रिकेटरों को लाभ होगा। बोर्ड की चेयरपर्सन डायना पुकेटापु-लिंडन ने कहा, अब हमारे 21 साल पुराने सुपर स्मैश टूर्नामेंट को फिर से जिंदा करने का समय है। शुरुआती प्रस्ताव में कई बदलावों की जरूरत होगी, खासकर नए टूर्नामेंट में महिलाओं के खेल की स्थिति के संबंध में। यह लीग आर्थिक रूप से बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाएगी और युवाओं को वैश्विक मंच प्रदान करेगी।

एशियाई टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप स्थगित

कराची। इस्लामाबाद में अगले महीने होने वाली एशियाई टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप खाड़ी में जारी संघर्ष के कारण स्थगित कर दी गई है। यह चैंपियनशिप 14 से 18 अप्रैल के बीच होनी थी। एक अधिकारी ने बताया, एशियाई स्क्वॉश महासंघ ने हमें बताया कि संघर्ष के कारण क्षेत्र के मौजूदा हालात को देखते हुए इस समय यह टूर्नामेंट करा पाना संभव नहीं है। हालात सुधरने पर पाकिस्तानी स्क्वॉश महासंघ सितंबर में इसे करा सकता है। यह पूछने पर कि क्या भारतीय स्क्वॉश महासंघ ने टीम भेजने पर मंजूरी दी थी, अधिकारी ने कहा कि टीमों की भागीदारी की पुष्टि एशियाई महासंघ देख रहा है।

पैक्ट खिलाड़ी नियम पसंद नहीं : अक्षर

एजेंसी । नई दिल्ली

भारतीय हरफनमौला और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने आईपीएल के 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम की आलोचना करते हुए कहा, मुझे यह पसंद नहीं क्योंकि इससे उनके जैसे खिलाड़ियों (हरफनमौला) के विकास में बाधा आती है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या भी इस नियम के खिलाफ बोल चुके हैं, जिसके तहत टीमें मैच के किसी भी समय अपनी एकादश में किसी खिलाड़ी को सूचीबद्ध पांच खिलाड़ियों में से किसी एक से बदल सकती हैं। यह नियम 2023 में लागू हुआ था।

भारतीय इंडोर एथलेटिक्स के नए युग की शुरुआत

एजेंसी । भुवनेश्वर

भारत इंडोर एथलेटिक्स में अपने सफर की औपचारिक शुरुआत मंगलवार से यहां शुरू हो रही पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के जरिये करेगा जो दो दिन चलेगी। चैंपियनशिप में 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिनमें ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सबसे बड़े दल हैं।दो साल बाद इसी स्थान पर उसे विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करनी है। पिछले सप्ताह भारत को विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है जो इसी स्थान पर 3 से 5 मार्च, 2028 में होगी।

फर्राटा दौड़ 60 मीटर की

अधिकांश भारतीय एथलीटों, आयोजकों और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अधिकारियों के लिए यह नया अनुभव होगा। इंडोर स्पर्धा 200 मीटर के ट्रैक पर होगी। सबसे छोटी फर्राटा दौड़ 60 मीटर की है। ऊंची कूद, पोल वॉल्ट, लंबी कूद, त्रिकूद और शॉटपुट को इसमें शामिल किया गया है लेकिन भाला फेंक, चक्का फेंक या तारगोला फेंक जैसी थ्रो स्पर्धाएं नहीं होंगी। आउटडोर स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर, मोहम्मद अफजल और

प्रवीण चित्रावेल भी इसमें नजर आएंगे। दो दिन में पुरुष और महिला वर्ग में 11 स्पर्धाएं होंगी जिनमें 60 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 60 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, पोल वॉल्ट, लंबी कूद, त्रिकूद और शॉटपुट शामिल हैं।

बॉलीवुड

भूतों की दुनिया में लौटे अजय देवगन

अजय देवगन ने एक बार फिर हॉरर जॉनर में कदम रखने का फैसला किया है। जहां उनके प्रशंसक 'दृश्यम 3' और 'गोलमाल 5' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब अभिनेता फिर से भूतों की दुनिया में नजर आएंगे। यह फिल्म अजय की पिछली हॉरर फिल्मों 'भूत' (2003) और 'काल' (2005) के बाद उनकी वापसी का प्रतीक होगी। रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए 'सरदारजी' फ्रैंचाइज़ी के निर्देशक रोहित जुगराज के साथ हाथ मिलाया है। निर्माता कुमार मंगत के बैनर तले यह परियोजना हाई कॉन्सेप्ट हॉरर के रूप में विकसित की जा रही है। एक सूत्र ने बताया कि रकहानी में माहौल और डर का निर्माण इस फिल्म को पारंपरिक हॉरर फिल्मों से अलग बनाएगा।र फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर लंदन में की जाएगी, और प्री-प्रोडक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अजय और निर्माता टीम उत्कृष्ट कलाकारों की तलाश में हैं, ताकि स्क्रीन प्रेजेंस और भी दमदार बन सके। सहायक कलाकारों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बिना शीर्षक वाली इस फिल्म की शूटिंग जुलाई, 2026 से शुरू होने की संभावना है और इसे आने वाले साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक माना जा रहा है।

अदिति राव हैदरी पर फिदा हुए पति सिद्धार्थ

मुंबई में चल रहे एक फैशन वीक के आखिरी दिन, एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने रनवे पर अपनी अदाओं से समां बांध दिया। उनके पति सिद्धार्थ पहली लाइन में बैठकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। इस कपल ने एक अनोखे पल के साथ फैंस को रैंप पर और रैंप के बाहर, दोनों जगह अपने प्यार की झलक दिखाई। अदिति ने एक शानदार मिडनाइट ब्लू लहंगे में रनवे पर जबरदस्त एंट्री की। उनकी ड्रेस ने फैंस का ध्यान खींचा। इस ड्रेस में एक लहराता हुआ स्कर्ट था जिस पर बारीक प्रिंट बने थे। इसके साथ अभिनेत्री ने एक बोल्ड, ब्रालेट-स्टाइल का ब्लाउज पहना था जिसका गला काफी गहरा था। इसमें एक मॉडर्न टच देने के लिए, उन्होंने इस लुक के ऊपर एक लंबा, स्ट्रक्चर्ड ट्रेंच कोट पहना, जिससे पारंपरिक पहनावे को एक आधुनिक लुक मिला। उनके इस लुक को और भी खास बनाया एक शानदार सिल्वर चोकर ने। इसके साथ बारीक चेनें लटकी थीं। मैचिंग झुमकों ने इस लुक में और भी जान डाल दी। उन्होंने चमकदार मेकअप चुना, जिसमें गुलाबी गाल, स्मोकी आंखें और न्यूड लिप्स शामिल थे। वहीं, फूलों से सजे उनके

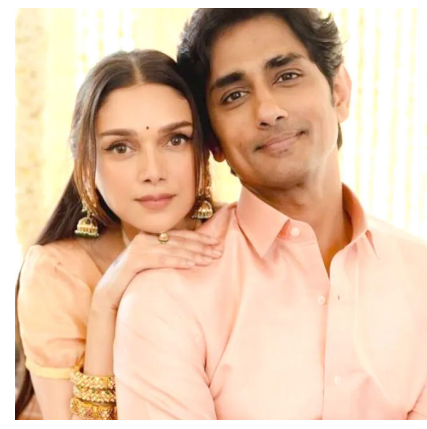

बालों ने इस लुक को रोमांटिक बना दिया। जहां अदिति ने रनवे पर पूरी तरह से अपना जलवा बिखेरा, वहीं सिद्धार्थ के साथ रैंप के बाहर बिताया गया उनका पल ही असली लाइमलाइट चुरा ले गया। पहली लाइन में बैठे एक्टर को अपनी पत्नी के लिए जाहिर तौर पर गर्व के साथ चीयर करते देखा गया। आदिति और सिद्धार्थ का एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है।

'हेरा फेरी 3' कॉपीराइट विवाद पर अब निर्माता विजय कुमार ने दी प्रतिक्रिया

फैंस को लंबे समय से इंतजार है 'हेरा फेरी 3' का, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की जोड़ी की वापसी होने वाली थी। लेकिन इस फिल्म का रास्ता अब कानूनी पचड़ों में फंस गया है। दक्षिण भारत के एक निर्माता और फिरोज नाडियाडवाला के बीच फिल्म के कॉपीराइट को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है। इसके कारण फिल्म की रिलीज़ पर अब संशय मंडरा रहा है। निर्माता विजय कुमार ने पिंकविला से बातचीत में दावा किया कि फिरोज नाडियाडवाला जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइजी के सभी अधिकार उनके पास हैं, लेकिन नाडियाडवाला ने बिना अनुमति दूसरी और तीसरी किस्त बनाने की कोशिश

की। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही अदालत से यह साबित कर दिया कि कॉपीराइट उनके स्वामित्व में हैं। विजय कुमार ने आगे कहा कि पहली फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए ही अधिकार दिए गए थे। दूसरी फिल्म बनाने के दौरान उनकी सहमति नहीं ली गई, और जब तीसरी फिल्म बनाने का प्रयास किया गया तो उन्हें नोटिस भेजा गया।

लंबे ब्रेक के बाद तब्बू साउथ सिनेमा में करेंगी वापसी

बॉलीवुड की दमदार अभिनेत्री तब्बू लंबे समय बाद साउथ सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फिल्म निर्माता पुरी जगन्नाथ की आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'स्लमडॉग-33 टेंपल रोड' का हिस्सा बनेंगी। इस फिल्म में उनके साथ विजय सेतुपति और संयुक्ता मेनन भी अहम भूमिकाओं में होंगे। यह हॉरर-कॉमेडी बताया जा रहा है कि फिल्म फिलहाल फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को में है और इसे इस साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज होने जा सकता है। गौरतलब है कि तब्बू के लिए तैयार है। वहीं, बार साउथ सिनेमा में अल्लू अर्जुन 'स्लमडॉग-33 टेंपल रोड' 'अला वैकुंठपुरमुलू' (2020) को उनके लिए सिर्फ एक देखा गया था। ऐसे में करीब फिल्म नहीं, बल्कि अपनी छह साल बाद उनकी जड़ों से दोबारा जुड़ने का यह वापसी फैंस के लिए मौका माना जा रहा है, खास मानी जा रही है। खासकर क्योंकि उनका उन्होंने अपने करियर हैदराबाद से गहरा जुड़ाव की शुरुआत तेलुगु रहा है। फिल्म 'कुली नंबर 1' (1991) से की थी और अब एक बार फिर उसी इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं।

इस बीच तब्बू जल्द ही बॉलीवुड फिल्म 'भूत बंगला' में भी नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में होंगे। यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं, 'स्लमडॉग-33 टेंपल रोड' को उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का मौका माना जा रहा है, खासकर क्योंकि उनका हैदराबाद से गहरा जुड़ाव रहा है।

वॉर ब्रीफ

मित्र देशों के लिए खुला है होर्मुज : ईरान

कोलंबो। श्रीलंका में ईरान के राजदूत अलीरेजा डेलखोशने सोमवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य मित्र देशों के लिए खुला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो तेहरान श्रीलंका को तेल या अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्रीलंका में ईरान के राजदूत ने कहा कि श्रीलंका हमारा मित्र देश है और जैसा कि मैंने आपको बताया, होर्मुज श्रीलंका जैसे हमारे दोस्तों के लिए बंद नहीं है।इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टारपीडो से डुबोए गए ईरानी युद्धपोत के बारे में बोलते हुए, दूत ने कहा कि वह पोत युद्ध के लिए यहां नहीं था।

जमीनी आक्रमण होने पर फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछाएंगे : ईरान

दुबई। ईरान की रक्षा परिषद ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर जमीनी आक्रमण हुआ, तो वह पूरे फारस की खाड़ी में समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। रक्षा परिषद का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब तेहरान में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि अमेरिकी मरीन नौसैनिक क्षेत्र में तैनात किए जा सकते हैं। रक्षा परिषद ने कहा कि दुश्मन द्वारा ईरान के तटों या द्वीपों को निशाना बनाने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से और स्थापित सैन्य प्रथाओं के अनुसार फारस की खाड़ी और तटीय इलाकों में पहुंच के सभी मार्गों को बारूदी सुरंगों से भर देने का कारण बनेगा। इस बीच, अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को ऊर्जा आपूर्ति के लिए फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है, जो फारस की खाड़ी का संकरा प्रवेश द्वार है। इस मिशन को समर्थन देने के लिए अमेरिकी मरीन नौसैनिक ईरान के द्वीपों या उसके तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए उतर सकते हैं। वहीं, इजरायल ने भी संकेत दिया है कि युद्ध के दौरान जमीनी अभियान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

एलपीजी लदे दो और भारतीय पोत होर्मुज पार करने को तैयार

नई दिल्ली। एलपीजी लदे दो और भारतीय पोत ने फारस की खाड़ी से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। उम्मीद है कि ये पोत युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ेंगे। एलपीजी टैंकर 'पाइन गैस' और 'जग वसंत' सोमवार दोपहर एक-दूसरे के करीब चलते हुए ईरान के लारक और केशम द्वीपों के बीच के पानी में थे। रिपोर्ट के अनुसार, जलडमरूमध्य पार करने से पहले ईरानी अधिकारियों को अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए वे वहां से गुजर रहे थे। फंसे 22 पोतों में शामिल हैं दोनों पोतये दोनों पोत उन 22 भारतीय ध्वज वाले पोतों में शामिल थे, जो पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने के बाद फारस की खाड़ी में फंस गए थे।

युद्ध के मुहाने पर ट्रंप का 'पॉज' बटन

ईरान पर हमले 5 दिन के लिए टले

एजेंसी । वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित हमलों को टालने का फैसला पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच एक बड़ी 'राजनयिक खिड़की' के रूप में देखा जा रहा है। 28 फरवरी 2026 को 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है जब दोनों पक्ष युद्ध के मैदान से हटकर बातचीत की मेज पर आते दिख रहे हैं। महज 48 घंटे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला, तो उसके पावर प्लांट्स को 'मिटा' दिया जाएगा। लेकिन सोमवार को उन्होंने अचानक अपने सुर बदलते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी सैन्य हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए जाएं। ट्रंप ने इसे 'बेहद सकारात्मक और उत्पादक बातचीत' का नतीजा बताया है।

अमेरिकी खजाने पर रोजाना आधा अरब डॉलर का बोझ

पिछले 24 दिनों से जारी इस जंग में अब तक ईरान में 2,000 से ज्यादा और इजरायल-अमेरिका के कई लोग मारे जा चुके हैं। ईरान का दावा है कि 81,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। इस युद्ध की वजह से अमेरिकी खजाने पर रोजाना आधा अरब डॉलर का बोझ पड़ रहा है, जिसने ट्रंप प्रशासन को समझौते के लिए सोचने पर मजबूर किया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि हमलों को रोकने का फैसला इस सप्ताह होने वाली वार्ताओं की सफलता पर निर्भर करेगा। अगर ईरान होर्मुज को पूरी तरह खोलने और अपनी सैन्य गतिविधियों को कम करने पर सहमत होता है, तो ही यह युद्ध खत्म हो पाएगा। फिलहाल, दुनिया की नज़रें ओमान में चल रही गोपनीय वार्ताओं पर टिकी हैं।

होर्मुज की नाकेबंदी और तेल का खेल

दुनिया के कुल तेल और गैस का करीब 20% हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में इसे बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। भारत जैसे देशों के लिए यह चिंता का विषय था, क्योंकि हमारे ऊर्जा टैंकर वहीं फंसे हुए थे। हालांकि, ईरान ने भारत,

'पॉवर प्लांट' बनाम 'पॉवर प्लांट' की धमकी

ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कलीबाफ ने साफ कहा था कि अगर उनके बिजली घरों पर हमला हुआ, तो वे पूरे खाड़ी क्षेत्र (यूएई, सऊदी अरब आदि) के ऊर्जा और जल संयंत्रों को निशाना बनाएंगे। इससे पूरे क्षेत्र में अंधेरा छाने और पानी का संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया था।

हमारी कड़ी चेतावनी के बाद पीछे हटा अमेरिका : ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के ऊर्जा प्लांट्स पर पांच दिन तक हमले रोकने के निर्देश पर तेहरान ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद पीछे हट गए हैं। बता दें कि, ट्रंप की तरफ से पहले दी चेतावनी की समय सीमा मंगलवार को लगभग सुबह छह बजे (भारतीय समयानुसार) पर समाप्त होनी थी। लेकिन ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने इसे पांच दिन बढ़ा दिया है। अर्ध-

सरकारी समाचार एजेंसी ने ईरान के विदेश मंत्रालय का एक बयान प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। बयान में कहा गया है कि ट्रंप की टिप्पणियां ऊर्जा की कीमतों को कम करने और अपनी सैन्य योजनाओं को लागू करने के लिए समय हासिल करने के उद्देश्य से की गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय देशों द्वारा तनाव कम करने के लिए पहल की जा रही है, लेकिन उन्हें अपनी बात वॉशिंगटन तक पहुंचानी चाहिए, जिसने इस युद्ध की शुरुआत की।

मिसाइलों की बौछार से 'टंगस्टन संकट' गहराया

ईरान पर हो रहे हमलों में इस्तेमाल हो रही मिसाइलें टंगस्टन भंडार को तेजी से खत्म कर रही

एजेंसी । लंदन

मध्य-पूर्व में जारी युद्ध का असर अब केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक धातु बाजार पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हो रहे हमलों में इस्तेमाल हो रही मिसाइलें अमेरिका के टंगस्टन भंडार को तेजी से खत्म कर रही हैं।

युद्ध ने बढ़ाया दबाव

ईरान युद्ध और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते पहले ही हथियारों और संसाधनों पर दबाव था। अब लगातार मिसाइल हमलों से टंगस्टन की खपत तेजी से बढ़ गई है, जिससे स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। टंगस्टन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। एमोनियम पैराटंगस्टेट (एपीटी) की कीमत एक साल में 400 डॉलर से बढ़कर 2,200 डॉलर प्रति टन से ऊपर पहुंच गई।

यूरोप में यहूदी समुदाय के प्रति बढ़ रहा है विरोध

लंदन। ईरान में जारी युद्ध की वजह से यूरोपीय देशों समेत दुनिया की कई जगहों पर एंटी सेमिटिज्म बढ़ रहा है। सोमवार को लंदन में एक यहूदी चैरिटी ट्रस्ट की चार एंबुलेंस को आग लगा दी गई। हालांकि इसे अभी आतंकी घटना घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जांच की जिम्मेदारी काउंटर-टेरर पुलिस को सौंपी गई है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर समेत कई धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस घटना को एक भयावह क्रूर यहूदी विरोधी हमला करार दिया।

ईरान पर इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हमले

रिहायशी इमारतों पर हमले में छह घायल

एजेंसी । तेहरान

इजरायल ने सोमवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर नए हमले किए, जिससे शहर के पूर्वी हिस्से से काले धुएं का घना गुबार उठता देखा गया। इसके बाद राजधानी में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई के संकेत दिए हैं, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान भी तेज कर दिया गया है।

रिहायशी इलाकों पर हमले

ईरानी समाचार एजेंसियों के अनुसार, पश्चिमी शहर खोर्रमबाद में रिहायशी इमारतों पर हुए हमलों में छह लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए। उत्तरी तेहरान के एक पॉश इलाके में स्थित इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जहां राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। हमलों के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

मोजतबा खामेनेई घायल

रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई घायल हैं और एकांत में हैं। बताया जा रहा है कि वे किसी भी संदेश का जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी एक अधिकारी ने उन्हें मामूली चोट लगने की पुष्टि की थी। वहीं, सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि रियाद की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से एक को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। जबकि दूसरी सुनसान इलाके में गिरी।

केरल में 'मुहर' पर महासंग्राम

- चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी का ठप्पा
- आयोग ने बताया लिखने की गलती
- क्या एक ही पावर सेंटर से चल रहे दोनों: विपक्ष

एजेंसी । तिरुवनंतपुरम

चुनाव आयोग के एक पुराने पत्र पर भाजपा केरल की मुहर पाए जाने के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले ने चुनावी निष्पक्षता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने इसे गंभीर चूक बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने इसे सिर्फ क्लेरिकल एरर यानी लेखन की गलती कहकर तुरंत सुधार करने की बात कही है। यह विवाद तब सामने आया जब सीपीआईएम ने सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज साझा किया, जिसमें 19 मार्च 2019 के चुनाव आयोग के पत्र के साथ लगे हलफनामे पर भाजपा केरल की मुहर दिखाई दी। इस पर कांग्रेस और सीपीआईएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग के केरल कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि यह गलती अनजाने में हुई और इसे तुरंत ठीक कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2019 के एक आधिकारिक पत्र से जुड़ा है, जो राजनीतिक दलों को भेजा गया था। सीपीआईएम ने दावा किया कि इस पत्र के साथ जो दस्तावेज भेजा गया, उस पर चुनाव आयोग की बजाय भाजपा की मुहर थी। पार्टी ने कहा कि यह दस्तावेज कई दलों को मिला और इसकी पुष्टि भी की गई। इससे यह सवाल उठने लगा कि क्या चुनाव आयोग के दस्तावेजों में बाहरी हस्तक्षेप हुआ है।

चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी?

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि यह पूरी तरह एक क्लेरिकल एरर था। भाजपा केरल यूनिट ने हाल ही में एक पुरानी गाइडलाइन की कॉपी जमा की थी, जिस पर उनकी मुहर लगी थी। इसी कॉपी को गलती से अन्य पार्टियों को भेज दिया गया। कार्यालय ने माना कि यह चूक नजरअंदाज होने की वजह से हुई और बाद में इसे तुरंत वापस ले लिया गया।

क्या कार्रवाई की गई?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जैसे ही गलती का पता चला, 21 मार्च को एक नया पत्र जारी कर गलत दस्तावेज वापस ले लिया गया। यह सूचना सभी राजनीतिक दलों, जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी गई। आयोग ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए सावधानी बरती जाएगी।

विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

सीपीआईएम और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि क्या अब चुनाव आयोग और भाजपा एक ही पावर सेंटर से चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल किया कि आयोग के पास भाजपा की मुहर कैसे पहुंची। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताया।

चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा?

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी और इससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आयोग ने कहा कि उसकी व्यवस्था पूरी तरह मजबूत और निष्पक्ष है। साथ ही लोगों और मीडिया से अपील की गई कि इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न किया जाए।

तीन राज्यों में शुरू होंगी सात कोयला गैसीकरण परियोजनाएं: रेड्डी

नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 64 हजार करोड़ रुपये के निवेश से सात कोयला गैसीकरण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे ऊर्जा उत्पादों के आयात में कमी लाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने कोयला क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने कोयला गैसीकरण गतिविधियां भी शुरू की हैं। सात परियोजनाएं शुरू होने जा रही। इनमें से चार परियोजनाओं का भूमिपूजन किया जा चुका है। सात परियोजनाओं में से चार महाराष्ट्र में, दो ओडिशा में और एक पश्चिम बंगाल में हैं। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के तहत कोयले को साइनगैस में बदला जाता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी), पेट्रोकेमिकल्स और तरल ईंधन बनाने में किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पेश

संयुक्त समिति को भेजा गया

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करना है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच वित्त मंत्री की सिफारिश पर इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और इसमें कई खामियां हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि इससे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कमजोर हो सकता है। डीएमके के सदस्यों ने भी विधेयक पेश किए जाने पर आपत्ति जताई और सरकार के इरादों पर सवाल उठाए।

सरकार का पक्ष : सुधार और सुगमता पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक दो वर्षों के व्यापक विचार-विमर्श के बाद लाया गया है और इसमें सभी पक्षों की राय शामिल की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएसआर में केवल शुद्ध मुनाफे से जुड़ी श्रेणी में बदलाव किया जा रहा है। विधेयक में छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और किसानों की उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाने, कुछ आपराधिक प्रावधानों को जुर्माने में बदलने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को इस विधेयक को मंजूरी दी थी।

साथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस

नौ पुलिसकर्मी दोषी करार

एजेंसी । चेन्नई

तमिलनाडु के चर्चित साथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में करीब छह साल बाद बड़ा फैसला आया है। मदुरै की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने पिता-पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। यह मामला 2020 में पूरे देश को झकझोर देने वाला था। अब अदालत ने साफ कर दिया है कि दोषियों को सजा भी मिलेगी, जिसकी घोषणा 9 अप्रैल को की जाएगी। अदालत ने व्यापारी पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स की मौत के मामले में इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल समेत सभी आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने कहा कि सबूतों और गवाहों के आधार पर यह साबित हुआ कि हिरासत में गंभीर यातना दी गई थी। यह फैसला लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे परिवार और देश के लिए अहम माना जा रहा है।

सजा पर 9 अप्रैल को आएगा फैसला

क्या था पूरा मामला और कैसे हुई मौत?

जून 2020 में लॉकडाउन के दौरान जयराज और उनके बेटे को दुकान देर तक खोलने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि थाने में दोनों को पूरी रात बेरहमी से पीटा गया और गंभीर यातनाएं दी गईं। हालत बिगड़ने के बावजूद उन्हें इलाज नहीं मिला और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई।

क्या जांच में सामने आईं चौंकाने वाली बातें?

जांच में खुलासा हुआ कि पुलिस ने रिकॉर्ड में हेरफेर किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान में गंभीर चोट और यातना की पुष्टि हुई। यहां तक कि गवाहों को डराने और दबाव बनाने की बात भी सामने आई।

केजरीवाल समेत आप नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश

नई दिल्ली। फांसी घर मामले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने सोमवार को द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की। उसमें दो बार समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने व बाद में उसका उचित स्पष्टीकरण न देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला को दोषी बताते हुए उनके विरुद्ध सदन द्वारा उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत की इस रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि चारों ने जानबूझ कर 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को आयोजित बैठकों में अनुपस्थित रहकर विशेषाधिकार समिति की अवमानना की है।

पिता-पुत्र की जंग में फंसा पीएमके का 'आम'

शीर्ष अदालत ने सिविल कोर्ट को सौंपी जिम्मेदारी

एजेंसी । नई दिल्ली/चेन्नई

तमिलनाडु की राजनीति में रसूख रखने वाली पार्टी पीएमके के भीतर 'वर्चस्व का युद्ध' छिड़ा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के भीतर चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि 'आम' चुनाव चिह्न पर मालिकाना हक का फैसला चुनाव आयोग नहीं, बल्कि सिविल कोर्ट करेगा।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, पीएमके संस्थापक रामदास अपने बेटे के खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी के नाम, झंडे और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कानूनी मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, पिछले साल रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद से ही दोनों गुटों में तलवारें खिंची हुई हैं। रामदास चाहते हैं कि चुनाव आयोग या तो उनके गुट को 'आम' का चिह्न आवंटित करे या फिर इसे पूरी तरह फ्रीज कर दे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह विवाद एक गैर-पंजीकृत राजनीतिक दल के भीतर का है। इसलिए चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा, ₹म हाई कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं पाते। चुनाव चिह्न के आवंटन का विवाद सिविल कोर्ट के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए।₹ हालांकि, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को देखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए।